नई सोच • नई शुरूआत • नया भारत

अनप्लग इंडिया

सच की आवाज, भारत की पहचान

नोएडा एनसीआर संस्करण

वर्ष : 01 | अंक : 43 | नोएडा, शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2026 | Website: www.unplugindia.com | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 03 रुपए

आज का विचार

‘कर्म करो, फल की चिंता मत करो।’ – मेहनत हमेशा मायने रखती है।



केजरीवाल को लॉरेंस गैंग से मिली धमकी फर्जी

पंजाब पुलिस का दावा-हरियाणा के कॉलर ने धमकाया

मोहाली (एजेंसी)। दिल्ली में तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने पुलिस को शिकायत दी है कि लॉरेंस गैंग ने अरविंद केजरीवाल से 7 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके फोन और वॉट्सऐप मैसेज के जरिए यह धमकी दी है। दिल्ली के तिलक नगर से एएपी विधायक जरनैल सिंह ने कहा- 6 नवंबर 2026 को शाम करीब 6 बजे उनके निजी मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से कॉल और वॉट्सऐप मैसेज आया। वॉट्सऐप प्रोफाइल पर नाम प्रदर्शित हो रहा था। आरोपी ने मैसेज में लिखा, लॉरेंस गैंग से हूं, अरविंद केजरीवाल को बोल दे 7 करोड़ दे दो नहीं तो अरविंद केजरीवाल और उसकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मार दूंगा। उनकी शिकायत पर मोहाली के साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज हुआ है। हालांकि, न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इन्वेस्टिगेशन में यह धमकी फर्जी पाई गई है।



घर में सोना कहां से आया महिलाओं को बताना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-500 ग्राम की लिमिट बताकर बच नहीं सकतीं

सर्वोच्च न्यायालय बोला-छापे के दौरान अधिकारियों को सोर्स बताएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में कई सालों से यह नियम चला आ रहा है कि अगर आयकर विभाग की छापेमारी हो, तो शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना होने पर अधिकारी उसे जब्त नहीं कर सकते।

इसी नियम का फायदा उठाकर कई लोग मान लेते थे कि 500 ग्राम तक सोना रखने पर किसी को कोई जवाब नहीं देना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने कहा- सोना जब्त न होना और उसका मालिक होना दो अलग बातें हैं। यह फैसला बिहार की एक पूर्व अफसर के मामले में आया, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। उन्होंने 500 ग्राम सोना होने का हवाला देकर



बचने की कोशिश की थी। बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी फूलपरी कुमारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला था। 2015 में बिहार विजिलेंस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच में उनके पास 646.400 ग्राम सोने के आभूषण मिले। उन्होंने दलील दी कि शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम और अविवाहित बेटी के लिए 250 ग्राम सोना जब्ती से सुरक्षित है। पटना हाईकोर्ट ने मई 2026 में उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी थी। बिहार सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही बहाल कर दी।

बंटवारे के बाद पोता दादा की संपत्ति का दावेदार नहीं

सुप्रीम कोर्ट बोला-वारिसों में बंटवारे के बाद पिता का हिस्सा निजी संपत्ति

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर दादा की संपत्ति उनके कानूनी वारिसों में बंट



चुकी है, तो पोता जन्म के आधार पर उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने 1997 में एक नाबालिग पोते की तरफ से दायर बंटवारे का मुकदमा खारिज कर दिया। फैसला 6 नवंबर को सुनाया गया, जिसकी जानकारी 11 नवंबर को सामने आई। मामला चेन्नई के 1,811 स्क्वायर फीट के एक मकान/प्लॉट का था। पोते का दावा था कि उसे जन्म से ही दादा की संपत्ति में कोपार्सनरी हक मिला है, इसलिए उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। यह मुकदमा नाबालिग पोते की ओर से दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बोला- ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को मिला हिस्सा पहले ही उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गया था। 1811 स्क्वायर फीट की यह संपत्ति चेन्नई में थी। मूल मालिक पोते के दादा थे। दादा की बेटी (पोते की बुआ) ने 1993 में बंटवारे का मुकदमा किया। फरवरी 1994 में समझौते से बंटवारा हो गया।

पंजाब में बीजेपी वर्सेज आप में बंट गए हैं ‘डेरे’

जालंधर (एजेंसी)। पंजाब के जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां में प्रबंधन और डेरा प्रमुख संत निरंजन दास के करीबी होने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। यहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी से जुड़े श्रद्धालुओं के दो गुट आमने-सामने हैं। विवाद की मुख्य वजह बीजेपी की प्रस्तावित समरसता संकल्प यात्रा है। इस यात्रा को डेरे से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। यह यात्रा 18 नवंबर को जालंधर से शुरू होकर 3 दिसंबर को वाराणसी में समाप्त होगी। इसका आयोजन 20 फरवरी 2027 को होने वाली गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के कार्यक्रमों के तहत किया जा रहा है। यह यात्रा पंजाब के अलावा जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से होकर गुजरेगी। पंजाब में होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और मुक्तसर जैसे जिलों को शामिल करने की योजना है। बीजेपी समर्थक रविदासिया श्रद्धालु चाहते हैं कि यात्रा की शुरुआत डेरा बल्लान से हो। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के शामिल होने की संभावना है।

यूपी में चंद्रशेखर-ओवैसी की पार्टियों में गठबंधन

सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, चंद्रशेखर सीएम फेस | प्रदेश में 40 फीसदी दलित-मुस्लिम वोट, दोनों की नजर

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन का ऐलान किया है। इसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रखा गया है।

गठबंधन यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। गुरुवार को लखनऊ में संयुक्त प्रेसवार्ता में ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर यूपी में सीएम का चेहरा होंगे। भाजपा को रोकने के लिए हमारा मोर्चा मजबूत विकल्प बनेगा। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि यह तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि पहला मजबूत मोर्चा होगा। बड़े गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन हमें कमजोर समझा गया। यूपी में मुस्लिम आबादी 19 फीसदी और दलित आबादी 21 फीसदी है। गठबंधन की नजर इसी 40 फीसदी आबादी के वोटों पर है। इस गठबंधन का सीधा असर सपा और बसपा के वोट बैंक पर पड़ सकता है। दोनों ने गठबंधन से सामाजिक परिवर्तन पार्टी का ऐलान किया है। अब गठबंधन यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन से यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमने सामाजिक परिवर्तन



मोर्चा बनाने का फैसला किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह भाजपा को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प होगा। **भाजपा को रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प बनेगा-** असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह मोर्चा भाजपा को रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प बनेगा। साथ ही दलितों और मुस्लिमों को राजनीतिक भागीदारी में बराबर का हक दिलाने की कोशिश करेगा। वहीं, चंद्रशेखर आजाद ने इसे तीसरा नहीं, बल्कि पहला मजबूत मोर्चा बताते हुए कहा कि अब राजनीतिक अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर ने घोषणा की कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ के माता रमाबाई मैदान में बहुजन समाज महासम्मेलन महारैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने मंच से असदुद्दीन ओवैसी को असद भाई कहकर इस महारैली में मजबूती के साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया।

शीतकालीन यात्रा में भी रजिस्ट्रेशन करवाने की तैयारी

चारधाम यात्रा में 2025 में पहुंचे थे 50 हजार श्रद्धालु | पर्यटन सचिव बोले- डाटा तैयार करने में मदद मिलेगी

देहरादून (एजेंसी)। चारधाम यात्रा का मुख्य सीजन अब समाप्त होने जा रहा है, लेकिन श्रद्धालु सर्दियों में भी चारों धामों के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऊंचाई पर स्थित मंदिरों तक जाने की जरूरत नहीं होगी।

शीतकाल में चारों धामों की उत्सव डोलियां अपने-अपने प्रवास स्थलों पर पहुंचेंगी, जहां अगले छह महीने तक पूजा-अर्चना और दर्शन होंगे। इधर, उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए पहली बार पंजीकरण व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। चारधाम यात्रा की तरह ही



शीतकाल में आने वाले श्रद्धालुओं का भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के पास यह जानकारी रहेगी कि किस प्रवास स्थल पर कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि, शीतकालीन यात्रा में चारधाम यात्रा की तुलना में भीड़ कम रहती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा। पर्यटन विभाग इस व्यवस्था को सुरक्षा के लिहाज से लागू करने पर विचार कर रहा है। पर्यटन सचिव धीराज गर्बयाल के मुताबिक, इससे शीतकालीन यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी और डाटा तैयार करने में मदद मिलेगी। चारधाम यात्रा में गंगोत्री के कपाट 10 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर दोपहर 12.05 बजे बंद हुए। इसके बाद 11 नवंबर को भाई दूज पर केदारनाथ के कपाट सुबह 8.30 बजे और यमुनोत्री के कपाट सुबह 10.28 बजे बंद किए गए। अब 16 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट रात 9.37 बजे बंद होंगे।

2024 में 73 हजार से अधिक 2025 में 50 हजार श्रद्धालु पहुंचे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना कर शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद शीतकाल में चारों धामों के प्रवास स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ाने के प्रयास किए गए। वर्ष 2024 में 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन किए थे। वहीं, 2025 में 50 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। सरकार का प्रयास है कि चारधाम यात्रा के छह महीने के सीजन के बाद भी प्रदेश में धार्मिक पर्यटन जारी रहे। इससे शीतकाल में भी स्थानीय कारोबारियों, होटल संचालकों, होमस्टे और टैक्सी कारोबार से जुड़े लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

घाटी से लापता दोनों स्पेशल पुलिस ऑफीसर के शव मिले

शरीर गोलियों से छलनी, हथियार भी गायब; सेना के साथ जंगल में सर्चिंग पर गए थे

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के मारवाह के जंगल में बुधवार शाम को लापता हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो एसएचओ के शव मिले हैं। दोनों शव गोलियों से छलनी हैं। उनके पास 60 राउंड वाली एक इंसास राइफल और 50 राउंड वाली एक 303 राइफल थी। दोनों के ही हथियार गायब हैं। दोनों आर्मी के साथ इलाके में सर्चिंग के लिए गए थे। जब वे लापता हुए थे, तब जंगल से फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी थीं। मृतकों की पहचान रशपाल कुमार और बाबी चंद के रूप में हुई है। दोनों एसएचओ के लापता होने के दौरान इसी इलाके में एयरटेल नेटवर्क सेवाएं बाधित होने की जानकारी भी सामने आई थी। एयरटेल कंपनी ने इसी साल 10 मार्च को मरवाह इलाके में पहली बार मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू की थी।





न्यूज की तरह जिंदगी में भी डेडलाइन है बेहद जरूरी

मोदी बोले-न्यूजरूम में कुछ भी असंभव नहीं माना जाता

पीएम बोले-सीएम बना तो मुझसे पहले मीडिया को पता था

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में दीपावली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यूजरूम में कुछ भी असंभव नहीं माना जाता। मोदी ने कहा कि भूकंप हो या बाढ़, जब लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं, तब रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में डालकर और परिवार की चिंता छोड़कर खबर की कवरेज करते हैं। न्यूज की दुनिया में डेडलाइन सबसे जरूरी होती है। उसी तरह जिंदगी में भी डेडलाइन जरूरी होती है। मोदी ने कहा- मैं 11 अशोका रोड पर पड़ा रहता था। एक दिन पत्रकार अचानक मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में मेरा गला पकड़ लिया और कहा कि मिठाई खिलाओ। मैंने पूछा कि किस बात की मिठाई खिलाऊं, तो उन्होंने कहा कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुझे खुद इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन पत्रकारों को पहले ही पता चल गया था। **पत्रकारों के साथ पुराने रिश्ते और मीडिया में बदलाव-** फैक्स से लेकर इंस्टाग्राम रील तक मीडिया का स्वरूप बदल चुका है। पहले खबरों की कवरेज ओबी वैन से होती थी, अब मोबाइल ही ओबी वैन बन गया है। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने की खबर पत्रकारों को उनसे पहले मिल गई थी। पत्रकारों ने उन्हें मिठाई खिलाने को कहा। कई पत्रकार अपने खर्चे पर शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंचे थे। पत्रकारिता में डेडलाइन से काम की प्राथमिकताएं तय होती हैं और रफ्तार बढ़ती है। देश के सामने भी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की डेडलाइन है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना होगा।



एमसीडी ने पूर्वी जिले में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की

निरीक्षण के दौरान अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से का जायजा लिया गया।

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पूर्वी जिले में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रभावशीलता का जायजा लेने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण के नोडल अधिकारी और आईएएस वी.के. बिधूड़ी ने गुरुवार को कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज स्थित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया।



निरीक्षण के दौरान अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से का जायजा लिया गया। इस दौरान एमसीडी की संयुक्त प्रवर्तन टीम की कार्यप्रणाली तथा यातायात प्रबंधन व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। निरीक्षण में मुख्य रूप से धूल नियंत्रण के उपायों, मिस्ट सिस्टम की कार्यशीलता एवं रखरखाव, सड़क की धूल के प्रबंधन, सार्वजनिक परिसरों की स्वच्छता तथा कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। निरीक्षण के दौरान मिस्ट सिस्टम के संचालन, रेलवे परिसर में धूल नियंत्रण के उपायों तथा कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण में कुछ कमियां पाई गईं। इसके अतिरिक्त रेलवे लाइन के किनारे कच्चे एवं बिना पक्के रास्तों की स्थिति तथा डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं उसके परिसर के रखरखाव का भी जायजा लिया गया। वी.के. बिधूड़ी ने सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ निरंतर एवं प्रभावी प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण के माध्यम से प्रशासन ने पूर्वी जिले में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जमीनी स्तर पर धूल प्रदूषण को नियंत्रित कर वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इस दौरान एमसीडी के उपायुक्त, पूर्वी जोन सहित दिल्ली यातायात पुलिस, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेलवे तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

महापौर ने भलस्वा लैंडफिल साइट का किया निरीक्षण

अबतक लगभग 1 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने गुरुवार को भलस्वा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर वहां चल रहे बायो माइनिंग एवं कचरे के निस्तारण कार्यों का जायजा लिया।



इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर जमा लीगेसी कचरे में से एक करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन लीगेसी कचरे का निस्तारण कर दिया गया है और अभी भलस्वा लैंडफिल साइट पर लगभग 23-25 लाख मीट्रिक टन लीगेसी कचरा बचा है जिसे तय समय सीमा में निस्तारित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर कचरा निस्तारण के लिए नई एजेंसी से अनुबंध किया गया है और अधिकारियों को कचरा निस्तारण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण कार्य की प्रगति रिपोर्ट की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी।

प्रवेश वाही ने बताया कि केंद्र और दिल्ली सरकार के सहयोग से भलस्वा लैंडफिल साइट पर जमा लीगेसी कचरे का निस्तारण कर लगभग 30 प्रतिशत एवं ओखला लैंडफिल साइट पर 60 प्रतिशत भूमि पुनः प्राप्त कर ली गई है जिसके उपयोग की योजनाओं के ऊपर कार्य चल रहा है।

महापौर ने कहा कि नए कचरे के निस्तारण कार्य में भी तेजी लाई जाएगी। कचरे के निस्तारण के लिए मशीनों की संख्या बढ़ाई जाएगी एवं कचरे के निस्तारण के लिए वज्र नाम की अत्याधुनिक मशीन को भी लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भलस्वा लैंडफिल साइट के कचरे के पहाड़ को तय समय में खत्म कर दिया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त संजीव खिरवार, अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार मित्तल एवं प्रसन्ना रामा स्वामी, उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त सचिन गुप्ता, बाहरी उत्तर क्षेत्र के उपायुक्त राघवेंद्र मीणा, प्रमुख अभियंता के.के.शर्मा सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

एमसीडी के सात अस्पतालों में पीपीपी मॉडल पर स्थापित होंगे डायलिसिस सेंटर

आयुष्मान भारत के पात्र लाभार्थियों को मिलेगी कैशलेस सुविधा

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के निगम के सात अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। निजी एजेंसी के साथ शुरुआती अनुबंध 10 वर्ष का होगा। एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने गुरुवार को विज्ञप्ति में बताया कि दिल्ली नगर निगम अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए किडनी के मरीजों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। निगम के सात अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे मरीजों को अपने नजदीकी निगम अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रावधानों के तहत कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

सत्या शर्मा ने कहा कि किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को नियमित रूप से डायलिसिस कराना पड़ता है। निजी अस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने पर करीब तीन हजार से 3500 रुपये तक खर्च होते हैं।

सप्ताह में दो से तीन बार डायलिसिस कराने वाले मरीजों और उनके परिवारों पर यह खर्च भारी आर्थिक बोझ बन जाता है। निगम का प्रयास है कि ऐसे मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कम दरों पर बेहतर उपचार का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।



उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में डायलिसिस केंद्र स्थापित होने से मरीजों को इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नियमित उपचार की जरूरत वाले मरीजों का समय और परिवहन पर होने वाला खर्च भी बचेगा। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को कैशलेस सुविधा मिलने से पात्र परिवारों को इलाज के खर्च की चिंता से भी राहत मिलेगी। सत्या शर्मा के अनुसार, स्वामी दयानंद अस्पताल, दिलशाद गार्डन, बाक राम अस्पताल, तिमारपुर, यूपीएचसी फतेहपुर बेरी, माता गुजरी अस्पताल, तिलक नगर, पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, कालकाजी, श्रीमती गिरधारी लाल मातृत्व अस्पताल, अजमेरी गेट और वीर सावरकर आरोग्य संस्थान, करावल नगर को शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि सातों केंद्रों का संचालन एक ही निजी सेवा प्रदाता को क्लस्टर मॉडल के तहत सौंपने का प्रस्ताव है। निजी एजेंसी अपने खर्च पर डायलिसिस मशीनें लगाएगी और तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था करने के साथ केंद्रों का संचालन एवं रखरखाव करेगी। उन्होंने बताया कि निगम प्रत्येक साइट के लिए महज एक रुपये प्रतिमाह के सांकेतिक लाइसेंस शुल्क पर जगह उपलब्ध कराएगा। पानी अस्पताल की मौजूदा व्यवस्था से मिलेगा, जबकि बिजली का खर्च एजेंसी को स्वयं उठाना होगा। निगम इस परियोजना के लिए सेवा प्रदाता को कोई प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करेगा और न ही मरीजों की संख्या की गारंटी देगा।

प्रस्ताव के अनुसार, निजी एजेंसी के साथ शुरुआती अनुबंध 10 वर्ष का होगा जिसे संतोषजनक प्रदर्शन और मशीनों के नवीनीकरण की शर्तों पर अधिकतम पांच वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा। पांचवें वर्ष में परियोजना की मध्यावधि समीक्षा होगी। एजेंसी का चयन खुली ई-टेंडर प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं में सबसे अधिक छूट देने वाले सेवा प्रदाता को काम सौंपने का प्रस्ताव है।

सत्या शर्मा ने कहा कि निगम का उद्देश्य अपने अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं को मजबूत करना और आम नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को मिली जान से मारने की धमकी

आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरा

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले ने दिल्ली की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने एक गुर्गे के जरिए अरविंद केजरीवाल को धमकी भरी कॉल करवाई है। वहीं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राजधानी में बढ़ते गैंगस्टरवाद और कारोबारियों से रंगदारी मांगने की घटनाओं को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा पंजाब को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले इस तरह की हरकतें कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने अपने गुर्गे से अरविंद केजरीवाल को धमकी भरा फोन करवाया है। संजय सिंह ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के खेल नहीं खेलने चाहिए। जब



अरविंद केजरीवाल भाजपा के आका से नहीं डरे तो इन बंदर घुड़की से क्या डरेंगे? उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियों से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं, सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले को दिल्ली की बिगड़ती कानून-व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तक को गैंगस्टरों की ओर से धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी में गैंगस्टरों द्वारा धमकी देना, कारोबारियों से फिरौती मांगना और उनसे फिरौती वसूलना अब आम बात होती जा रही है। इसके कारण दिल्ली के व्यापारियों और कारोबारियों में डर का माहौल बना हुआ है।

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दिल्ली के ज्यादातर कारोबारी गैंगस्टरों से मिलने वाली धमकियों की शिकायत सरकार और दिल्ली पुलिस से करना भी उचित नहीं समझते। उनका कहना है कि कारोबारियों को लगता है कि पुलिस या सरकार के पास शिकायत करने से भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसे में वे डर के माहौल में रहने और कई बार मजबूरी में फिरौती देने को विवश हो जाते हैं।

उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में ऐसे कई मामले हैं, जिनमें कारोबारियों ने फिरौती की धमकी मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिरौती की रकम देनी पड़ी।

दिल्ली में खुलेआम बिक रहे नशे पर सियासी घमासान, विधायक ने स्मैक खरीदकर डीएम के सामने रखा पैकेटः सौरभ भारद्वाज

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम बिक रहे नशीले पदार्थों को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने सरकार निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा की चार इंजन वाली सरकार में दिल्ली धीरे-धीरे नशे की नगरी बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी में नशे के कारोबार की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब भाजपा के अपने विधायक को भी प्रशासन को जगाने के लिए खुद स्मैक खरीदकर जिलाधिकारी के सामने उसका पैकेट रखना पड़ा है। गुरुवार को सौरभ भारद्वाज ने मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रोहतास नगर से भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार और प्रशासन का ध्यान नशे के खुले कारोबार की ओर आकर्षित करने के लिए स्मैक का एक पैकेट खरीदा और उसे जिलाधिकारी के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी दल के विधायक को नशे की बिक्री का सबूत जुटाकर अधिकारियों के सामने पेश करना पड़ रहा है तो इससे दिल्ली में कानून-व्यवस्था और नशे के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में ड्रग्स, गांजा, स्मैक और कोकीन समेत कई तरह के नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। विधायक, पार्षद और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि लगभग रोजाना इस संबंध में शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर, सीमापुरी और रोहतास नगर के अलावा उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के बवाना, सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी जैसे इलाके नशे के कारोबार से बुरी तरह प्रभावित हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला था।

पंजाबी बाग प्रदूषण हॉटस्पॉट का नोडल सचिव ने किया निरीक्षण

रेलवे सीमेंट साइडिंग यार्ड में आवाजाही पर लगाई रोक

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के नोडल सचिव रूपेश कुमार ठाकुर ने गुरुवार को पंजाबी बाग स्थित वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट का निरीक्षण कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रेलवे सीमेंट साइडिंग यार्ड में पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन का जायजा लिया और संबंधित विभागों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि नोडल सचिव ने 28 अक्टूबर को किए गए पिछले निरीक्षण के दौरान रेलवे सीमेंट साइडिंग यार्ड से उड़ने वाली धूल के कारण हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यार्ड को सील करने सहित कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की स्थिति जानने के लिए उन्होंने गुरुवार को दोबारा संबंधित स्थल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रेलवे प्रशासन ने यार्ड में बैरिकेडिंग कर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल की एक चौकी स्थापित करने के साथ जवानों की तैनाती भी की गई है, ताकि परिसर में किसी भी प्रकार की अनधिकृत



आवाजाही और गतिविधियों को रोका जा सके। नोडल सचिव ने इन व्यवस्थाओं को धूल प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

ठाकुर ने पंजाबी बाग हॉटस्पॉट के अलावा अन्य स्थानों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, सड़कों पर उड़ने वाली धूल, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों, कचरे के जमाव तथा प्रदूषण के अन्य स्थानीय स्रोतों की स्थिति की समीक्षा की।

निरीक्षण के बाद दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें अधिकारियों ने हॉटस्पॉट की मौजूदा स्थिति, विभिन्न विभागों की ओर से किए गए कार्यों और आगे प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों की जानकारी दी।

नोडल सचिव ने सभी संबंधित विभागों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त एवं निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करने, आपसी समन्वय मजबूत बनाने और चिह्नित प्रदूषण स्रोतों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता हो, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। वर्तमान प्रदूषण सीजन में वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट को देखते हुए सभी विभाग सतर्क और सक्रिय रहें।

निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक के दौरान दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र के उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री, सहायक आयुक्त स्वप्निल सिंह ठाकुर सहित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली जल बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

दिल्ली नगर निगम ने छठ घाटों की तैयारियों का किया व्यापक निरीक्षण

सफाई और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम ने राजधानी के विभिन्न छठ घाटों पर तैयारियों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को घाटों पर साफ-सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, धूल नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए।

पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत और विधायक एवं डीडीसी चेयरमैन प्रद्युम्न राजपूत ने क्षेत्रीय पार्षदों तथा दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के उपायुक्त शशि प्रताप सिंह के साथ सागरपुर और महावीर एन्क्लेव स्थित छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान घाटों पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र की वार्ड समिति के अध्यक्ष हरीश ओबेरॉय ने पश्चिमी क्षेत्र के उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री के साथ विभिन्न छठ घाटों का



निरीक्षण किया। उन्होंने विकासपुरी के न्यू कृष्णा पार्क स्थित छठ घाट पर जल एवं प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया।

पूर्वी क्षेत्र के उपायुक्त अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी ने विभागाध्यक्षों के साथ आईटीओ के पास स्थित हाथी घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान नदी किनारे कुछ स्थानों पर कचरा जमा होने और यमुना में तैरता हुआ कचरा दिखाई देने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर यांत्रिक नौकाओं के माध्यम से नदी में तैरते कचरे को हटाने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्माण एवं विध्वंस (सीएएंडडी) कचरे का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके लिए जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। घाटों पर धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव करने की योजना भी बनाई गई है।

निगम अधिकारियों को छठ पूजा से पहले, पूजा के दौरान और पूजा के बाद तक के लिए विस्तृत स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत घाटों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने, पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगाने, पूजा सामग्री के पृथक संग्रहण एवं उचित निस्तारण तथा प्रमुख स्थानों पर स्वच्छता संबंधी जागरूकता संदेशों वाले सूचना बोर्ड लगाने को कहा गया।

निगम ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।

संक्षिप्त डायरी

बहनों ने भाइयों का तिलक कर लंबी उम्र की कामना

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी में बुधवार को भैयादूज पर्व को धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारी। भाइयों की लंबी उम्र के लिए मंगलकामना भी की। पर्व को लेकर सुबह से ही घरों में उत्साह का माहौल रहा। भाईयों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और लंबी उम्र की कामना की गई। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर हर रक्षा का संकल्प लिया। इस मौके पर बाजारों में खासी भीड़ रही। भैयादूज पर बहनों ने अपने भाइयों की सुख समृद्धि की मंगलकामना करते हुए व्रत रखा। कहीं बहनें अपने भाइयों के घर भैया दूज मनाने के लिए पहुंचीं, तो कहीं भाई अपनी बहनों के घर पहुंचे। शहर के विभिन्न बाजारों में उपहार, पूजा सामग्री के अलावा मिठाइयों की दुकानों पर भी खासी भीड़ बनी रही। बहनों ने अपने भाइयों का रोली चावल से तिलक किया। आरती उतारी और मिठाई खिलाई। किसी ने अपने भाई को उनकी पसंद के उपहार तो किसी ने भाई की पसंद के लजीज व्यंजन बनाकर उन्हें खुश किया। खूबसूरत उपहारों के साथ-साथ कहीं भाई अपनी बहनों को उनकी पसंद की शॉपिंग करवाते हुए भी नजर आए। शहर के मुख्य बाजारों के साथ-साथ शॉपिंग मॉल्स में भी खरीदारी करने वालों की खासी संख्या रही।

सीएंडडी वेस्ट प्रबंधन को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चलाया जागरूकता अभियान

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम । शहर में बढ़ते प्रदूषण और निर्माण मलबे के बेतरतीब फैलाव पर रोक लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गुरुग्राम उत्तर क्षेत्रीय टीम ने अब प्रवर्तन के साथ-साथ जागरूकता का मोर्चा भी संभाल लिया है। बोर्ड ने उद्योग विहार क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर बिल्डरों, निर्माणकताओं और ठेकेदारों को गत एक अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए नए पर्यावरण नियमों की जानकारी दी। अभियान के दौरान सहायक पर्यावरण अभियंता कामेश और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता राघवेंद्र ने स्पष्ट किया कि निर्माण स्थलों पर निकलने वाले मलबे का वैज्ञानिक प्रबंधन अब कानूनी रूप से अनिवार्य है। बोर्ड के स्वच्छ और हरित हरियाणा के लिए मिलकर प्रयास अभियान के तहत अधिकारियों ने बताया कि सभी निर्माण परियोजनाओं को आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कराने के साथ नियमित रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके अलावा, स्रोत पर ही मलबे को अलग करना, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का पालन करना और निर्माण कार्यों में रीसाइकिल सामग्री का उपयोग करना जरूरी है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि मलबे को इधर-उधर फेंकने के बजाय केवल अधिकृत प्रसंस्करण केंद्रों पर ही भेजा जाए और इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भारी जुमार्ने और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2027 विधानसभा चुनाव में मेट्रो बनेगा भाजपा का मास्टर कार्ड

अनप्लग इंडिया

नोएडा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी तैयारियां तेज होने लगी हैं। ऐसे में नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलना भाजपा के लिए अहम चुनावी मुद्दा बन सकता है। सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक 8.449 किमी लंबे मेट्रो कॉरिडोर और पांच नए एलिवेटेड स्टेशन बनाने की मंजूरी को पार्टी विकास के एजेंडे के रूप में जनता के बीच ले जा सकती है। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक भी मेट्रो विस्तार की योजना है। इन परियोजनाओं का राजनीतिक असर खासतौर पर नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो विस्तार की मांग कई वर्षों से उठ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में रहा था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बड़ी आबादी लंबे समय से मेट्रो सुविधा की मांग कर रही है। चुनाव के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने भी यह मांग उठाई गई थी। अब केंद्रीय कैबिनेट से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद भाजपा को इस मांग पर निर्णय लेने का श्रेय लेने का अवसर मिल गया है। परियोजना का राजनीतिक महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि इसका लाभ केवल नोएडा तक सीमित नहीं रहेगा। सेक्टर-51, सेक्टर-61, सेक्टर-70, सेक्टर-122, सेक्टर-123 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आवासीय क्षेत्रों को इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। इन इलाकों में बड़ी संख्या में नौकरीपेशा परिवार, युवा और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसे में मेट्रो विस्तार को आवागमन की समस्या और शहरी सुविधाओं से जोड़कर चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। नोएडा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा इसे शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार और बेहतर परिवहन सुविधा के रूप में पेश कर सकती है। वहीं, दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रेटर नोएडा वेस्ट और आसपास के इलाकों में परियोजना की मंजूरी को विकास के प्रयासों से जोड़कर पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करेगी। जेवर विधानसभा क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, औद्योगिक विकास और सड़क कनेक्टिविटी पहले से ही प्रमुख मुद्दे हैं। ऐसे में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को एनसीआर की व्यापक परिवहन योजनाओं से जोड़कर भाजपा क्षेत्रीय विकास का एजेंडा सामने रख सकती है। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश और मेट्रो जैसी परियोजनाओं को एक साथ रखकर पार्टी मतदाताओं के बीच विकास कार्यों को प्रमुखता दे सकती है। मेट्रो विस्तार को मंजूरी मिलने से भाजपा को चुनावी मुद्दा जरूर मिल सकता है, लेकिन विपक्ष भी इस पर सवाल उठाने की तैयारी में रहेगा। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस परियोजना की घोषणा और धरातल पर निर्माण शुरू होने के बीच के अंतर को मुद्दा बना सकती हैं। विपक्ष की ओर से यह सवाल उठाया जा सकता है कि निर्माण कार्य कब शुरू होगा, परियोजना कब पूरी होगी और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सभी प्रभावित आवासीय क्षेत्रों तक मेट्रो की सुविधा कब पहुंचेगी। - क्षेत्रवासियों की बहुत लंबे समय से लंबित मांग और जरूरत आज पूरी हुई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो पास होने पर ग्रेटर नोएडा वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। - डॉ. महेश शर्मा, सांसद गौतमबुद्ध नगर - यह परियोजना लाखों नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा। व्यावसायिक केंद्रों, शिक्षण संस्थानों तथा अस्पतालों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। - पंकज सिंह, विधायक नोएडा - बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नोएडा ग्रेटर नोएडा के विकास को पंख लगेगा और आवागमन सुलभ होगा। - सुरेंद्र सिंह नागर, सांसद राज्यसभा मेट्रो कनेक्टिविटी से प्रतिदिन नोएडा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में नौकरी, व्यापार, शिक्षा एवं अन्य कार्यों के लिए आने-जाने वाले लाखों लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। - तेजपाल सिंह नागर, विधायक दादरी

आर्थिक गतिविधियों का गलियारा भी बनेगा नया मेट्रो रूट

अनप्लग इंडिया

नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का नया मेट्रो रूट आवागमन के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। डीपीआर में रोजगार, कारोबार, शिक्षा और यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस कॉरिडोर के आसपास कई बड़े मॉल, आईटी कंपनियों के कार्यालय, अस्पताल और शिक्षण संस्थान हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौड़ सिटी मॉल और एच एंड एस मॉल, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 में ब्लू सफायर मॉल और गोल्डन आई के व्यावसायिक परिसर हैं। नोएडा के सेक्टर-73 में एंथुरियम मॉल, सेक्टर-75 में स्पेक्ट्रम मॉल और सेक्टर-51 में प्रस्तावित आइकिया शॉपिंग सेंटर भी प्रमुख व्यावसायिक केंद्र हैं। इसके अलावा सेक्टर-60 में टेक महिंद्रा और टीसीएल टेक के कार्यालय, सेक्टर-73 में तेल उद्योग विकास बोर्ड और सेक्टर-122 में दिल्ली पब्लिक स्कूल स्थित है। सेक्टर-50, 51, 62 और 70 के आसपास कई बड़े निजी अस्पताल भी हैं।

भूटान के 40 शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का प्रशिक्षण देगा एमिटी विश्वविद्यालय, पांच दिवसीय टीचर इमर्शन प्रोग्राम शुरू

अनप्लग इंडिया



नोएडा। अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एमिटी विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। विश्वविद्यालय के एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ओर से रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के शिक्षकों के लिए पांच दिवसीय टीचर इमर्शन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। 12 से 16 नवंबर, 2026 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भूटान के 40 स्कूली शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष रूप से इस तरह तैयार किया गया है कि भूटान के शिक्षक अंतरराष्ट्रीय स्कूली शिक्षा मानकों और खासतौर पर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल एजुकेशन फ्रेमवर्क की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसके माध्यम से शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक तौर-तरीकों, नवीन शिक्षण तकनीकों और वैश्विक शिक्षा प्रणाली से परिचित कराया जाएगा।

कार्यक्रम का उद्घाटन एमिटी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉ. बलविंदर शुक्ला और एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्रमुख प्रो. (डॉ.) अल्का मुद्गल ने किया।

भूटान में लागू हुआ कैम्ब्रिज पाठ्यक्रम, शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

उद्घाटन सत्र के दौरान भूटान की स्कूली शिक्षिका सुश्री येशी चोडेन वांगमो ने कार्यक्रम की उपयोगिता पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि भूटान में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही कैम्ब्रिज पाठ्यक्रम लागू किया गया है। ऐसे में एमिटी विश्वविद्यालय का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वहां के शिक्षकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य कैम्ब्रिज पाठ्यक्रम को गहराई से समझना, प्रभावी शिक्षण पद्धतियों को सीखना और उन्हें अपनी कक्षाओं में लागू करना है। इसके साथ ही शिक्षक यह भी जानना चाहते हैं कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने नवीन शिक्षण तकनीकों को सीखने की उत्सुकता भी जाहिर की, ताकि कैम्ब्रिज पाठ्यक्रम के अनुरूप उन्हें भूटान के स्कूलों में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

शिक्षक भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करते हैं : डॉ. बलविंदर शुक्ला

एमिटी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉ. बलविंदर शुक्ला ने भूटान से आए सभी शिक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि युवा मस्तिष्कों को आकार देने और भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।

उन्होंने कहा कि टीचर इमर्शन प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने, ज्ञान के आदान-प्रदान और वैश्विक अनुभवों के माध्यम से शिक्षकों के पेशेवर विकास के प्रति एमिटी विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. शुक्ला ने कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षकों को अपने अनुभव साझा करने, एक-दूसरे से सीखने और शिक्षण-सीखने की आधुनिक एवं नवीन पद्धतियों को समझने का अवसर प्रदान करेगा। कार्यशालाओं और विशेषज्ञों के सत्रों से मिलेगा व्यावहारिक अनुभव

सरकार को माननी पड़ेंगी छात्रों की जायज मांगें: आफताब अहमद

अनप्लग इंडिया

नूंह। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद मंगलवार देर रात पल्ला गांव स्थित मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज के धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि भूख हड़ताल पर बैठे छात्र अपने हक और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। वहीं, कॉलेज के शिक्षक और अन्य कर्मचारी भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम के सिलसिले में केरल गए हुए थे। इससे पहले भी उन्होंने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपकर कॉलेज की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की थी। इसके बावजूद अब तक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब सरकार और प्रशासन को पहले से ही कॉलेज की समस्याओं की जानकारी थी, तो समय रहते उनका समाधान क्यों नहीं किया गया। बाद में हरियाणा सरकार के मंत्री भी धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों से कुछ समय देने की अपील की। आफताब अहमद ने कहा कि आज दोबारा छात्रों के बीच पहुंचने पर उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि कुछ लोग छात्रों पर दबाव बनाकर उनका धरना समाप्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी सभी मांगें जायज हैं। सरकार को छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी ने छात्रों को जबरदस्ती धरने से हटाने या उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़ी रहेगी।

यशोदा हाफ मैराथन 4.0 की तैयारियां तेज: 22 नवंबर को दौड़ेंगे 4 हजार से अधिक प्रतिभागी, टी-शर्ट और फिनिशर मेडल का अनावरण

अनप्लग इंडिया

गाजियाबाद। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, हृदय की देखभाल और नियमित शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली यशोदा हाफ मैराथन 4.0 की तैयारियां तेज हो गई हैं। 22 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली इस मैराथन से पहले यशोदा मेडिसिटी ने गुरुवार को आधिकारिक टी-शर्ट और फिनिशर मेडल का अनावरण किया। इस बार मैराथन में 4,000 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है।

'रन फॉर योर हार्ट' थीम पर आयोजित होने वाली इस मैराथन का उद्देश्य लोगों को हृदय स्वास्थ्य, बचाव आधारित चिकित्सा और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है। पिछले आयोजनों में मिली भागीदारी के बाद इस बार भी बड़ी संख्या में धावकों, फिटनेस प्रेमियों और परिवारों के शामिल होने की संभावना है।

कई प्रमुख अतिथियों की मौजूदगी में हुआ टी-शर्ट और मेडल का अनावरण

टी-शर्ट और फिनिशर मेडल के अनावरण समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील कुमार शर्मा, गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदार (ट्वीस्), ट्रांस हिंडन के पुलिस उपायुक्त रिजू और रेडिसन ब्लू कौशांबी के सीईओ नवनीत जैन शामिल हुए। इन अतिथियों ने यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉ. पी.एन. अरोड़ा और अस्पताल की नेतृत्व टीम के साथ मैराथन की आधिकारिक टी-शर्ट और फिनिशर मेडल का अनावरण किया।

अतिथियों ने कहा कि इस तरह के सामुदायिक आयोजन लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

एलिवेटेड रोड पर होगी मैराथन, चार श्रेणियों में दौड़

यशोदा हाफ मैराथन 4.0 का आयोजन गाजियाबाद की प्रसिद्ध एलिवेटेड रोड पर किया जाएगा। इसमें अलग-अलग आयु और फिटनेस स्तर के लोगों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए चार श्रेणियां रखी गई हैं।

मैराथन की चार श्रेणियां

21.1 KM
हाफ मैराथन
10 KM
10 किलोमीटर दौड़
5 KM
5 किलोमीटर दौड़
3 KM
फन रन

रूट में यू-टर्न की व्यवस्था

21.1 किमी: 6 और 15 किमी पर
10 किमी: 5 किमी पर
5 किमी: 2.5 किमी पर
3 किमी फन रन: 1.5 किमी पर

चारों श्रेणियों के लिए सिंगल-लूप रूट निर्धारित किए गए हैं।

विजेताओं को मिलेगा 11 हजार रुपये तक का नकद पुरस्कार

मैराथन की प्रतिस्पर्धी श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। आयोजकों की ओर से घोषित पुरस्कार राशि इस प्रकार है:

श्रेणी	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान
21.1 किमी	11,000	7,100	5,100
10 किमी	7,100	5,100	3,100
5 किमी	5,100	3,100	2,100

3 किलोमीटर की श्रेणी को फन रन के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सामुदायिक फिटनेस गतिविधि से जोड़ना है।

स्वास्थ्य के लिए जरूरी है नियमित शारीरिक गतिविधि : सुनील कुमार शर्मा

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि यशोदा हाफ मैराथन जैसे आयोजन लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट करते हैं। फिटनेस को बढ़ावा देना और बचाव आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी है।

उन्होंने कहा कि यशोदा मेडिसिटी की यह पहल अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रही है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदार ने कहा कि ऐसे आयोजन लोगों को फिटनेस को प्राथमिकता देने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनके माध्यम से अनुशासन, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिलता है।

अस्पताल की चारदीवारी से बाहर भी स्वास्थ्य जागरूकता जरूरी : डॉ. पी.एन. अरोड़ा

यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉ. पी.एन. अरोड़ा ने कहा कि हृदय स्वास्थ्य पर ध्यान केवल बीमारी के लक्षण सामने आने या चिकित्सा की जरूरत पड़ने के बाद नहीं देना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से बचाव, जागरूकता और दैनिक जीवनशैली में सुधार जरूरी है।

उन्होंने कहा कि यशोदा हाफ मैराथन 4.0 के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि नियमित शारीरिक गतिविधियां अच्छे स्वास्थ्य और हृदय की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

डॉ. अरोड़ा के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा अस्पताल की चारदीवारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए स्वयं भी सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को बढ़ावा देने की पहल-यशोदा मेडिसिटी के अनुसार, यशोदा हाफ मैराथन उसकी व्यापक प्रिवेंटिव हेल्थकेयर (बचाव आधारित स्वास्थ्य सेवा) पहल का हिस्सा है। इसके तहत लोगों को बीमारी का इलाज कराने के साथ-साथ समय रहते स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, नियमित जांच और बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर नर्सिंग ऑफिसर्स में उठे विरोध के स्वर

अनप्लग इंडिया



गुरुग्राम। हरियाणा में नर्सिंग ऑफिसर्स ने ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में एक बार फिर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य प्रधान विनीता बांगड़ ने बुधवार को कहा कि सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ धोखा किया है। बिना सूचित किए ट्रांसफर का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। अब सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। विनीता बांगड़ ने कहा कि ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में नर्सिंग ऑफिसर्स ने पांच-छह अक्टूबर 2026 को हड़ताल की थी। उस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डा. सुमिता मिश्रा ने इस आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कराई थी कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष नर्सिंग ऑफिसर्स पर यह पॉलिसी लागू नहीं करने की सिफारिश करेंगी। इसके बाद इस पर क्या निर्णय हुआ, क्या चर्चा हुई, इसकी कोई जानकारी नर्सिंग एसोसिएशन को नहीं दी गई। अब अचानक बिना सूचित किए ट्रांसफर के आदेश निकाल दिए गए हैं। यह नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ सरासर धोखा है। अब अनिश्चिकालीन हड़ताल होगी। क्योंकि जबरन ट्रांसफर पॉलिसी थोपकर सरकार नर्सिंग ऑफिसर्स को अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है। जल्द ही हड़ताल की तारीख तय की जाएगी। हड़ताल में जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने सभी नर्सिंग ऑफिसर्स से एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेने की अपील की है। विनीता बांगड़ ने बताया कि हरियाणा के सभी जिलों के नर्सिंग एसोसिएशन प्रधान अपने-अपने जिलों में 14 नवंबर 2026 तक मीटिंग रखेंगे। सभी जिलों से सुझाव लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। विनीता बांगड़ ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, रात में परिवहन की सुविधा का ख्याल नहीं रख रही। नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी आम कर्मचारियों यानी अन्य विभागों के कर्मचारियों से बिल्कुल अलग है। हमारी कोई 9 से 5 बजे की ड्यूटी नहीं है। सुबह, दोपहर, रात का ड्यूटी शेड्यूल रहता है। हम 24 घंटे की सेवा देते हैं। इसलिए सरकार आवासीय सुविधा दे। बच्चों की एडमिशन फीस सरकार वहन करे, जो तबादला होने पर दूसरे जिलों में देनी पड़ेगी। केंद्र के समान नर्सिंग अलाउंस दिया जाए।

नूंह: 41वें दिन मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज का आंदोलन पड़ा ठंडा, कैंपस से गायब हुई भीड़

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। नूंह के पल्ला गांव स्थित मेवात वक्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले 40 दिनों से जारी आंदोलन के 41वें दिन बुधवार को माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। जिस कॉलेज परिसर में पिछले कई दिनों से भारी भीड़, नारेबाजी और हंगामा दिखाई दे रहा था, वहां आज सन्नाटा पसरा रहा। आंदोलन के दौरान बाहर से आए लोगों की भीड़ भी अब कॉलेज परिसर में दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा पहचान कर बाहरी लोगों को कॉलेज कैंपस से बाहर किए जाने के बाद अब परिसर में मुख्य रूप से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ही नजर आ रहे हैं। धरना स्थल की तस्वीर भी बदली हुई दिखाई दी। जहां पहले बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठते थे, वहीं बुधवार को कुछ ही छात्र इधर-उधर बैठे नजर आए। इसके अलावा कॉलेज के कुछ लेक्चरर और कर्मचारी भी धरना स्थल पर मौजूद रहे। पूरे कॉलेज परिसर में न तो पहले जैसी नारेबाजी सुनाई दी और न ही किसी तरह का हंगामा देखने को मिला। छात्र सामान्य रूप से कॉलेज परिसर में बैठे दिखाई दिए। आंदोलन के इस बदले माहौल की एक बड़ी वजह मंगलवार को हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासन की ओर से छात्रों की सभी मांगों को लिखित रूप में मंजूरी दिया जाना माना जा रहा है। मांगों पर सहमति बनने के बाद कुछ छात्रों ने आंदोलन को लेकर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि उनकी मांगें मान ली गई हैं। वहीं कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि उन्हें इस आंदोलन में इस्तेमाल किया गया, जिसका उन्हें अफसोस है। वहीं कॉलेज के लेक्चरर का कहना है कि यह आंदोलन पिछले 40 दिनों से चल रहा है और बुधवार को 41वां दिन है। आंदोलन शुरू करने के पीछे छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और कॉलेज के स्टाफ को समय पर वेतन दिलाने की मांग प्रमुख थी। इस संबंध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया था। ज्ञापन में मांग की गई थी कि यदि वक्फ बोर्ड कॉलेज का संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो इसे हरियाणा सरकार के अधीन कर दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और शिक्षकों व कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके।

ग्रेटर नोएडा में रेरा के 77.66 करोड़ रुपये बकाया पर तीन निदेशक गिरफ्तार, कई बार सील हो चुके थे कंपनी के दफ्तर

अनप्लग इंडिया। डेस्क



ग्रेटर नोएडा। रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) का करोड़ों रुपये का बकाया नहीं चुकाने वाले बिल्डर कंपनियों के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 77 करोड़ 66 लाख रुपये से अधिक की बकाया रकम जमा नहीं करने पर प्रशासन ने तीन निदेशकों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को दादरी तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।

गिरफ्तार किए गए निदेशकों की पहचान श्री राम, मोहम्मद अलीम और तस्लीम सिद्दीकी के रूप में हुई है। ये तीनों अंसल हाईटेक टाउनशिप्स लिमिटेड और उत्तम स्टील्स एसोसिएट्स लिमिटेड से जुड़े बताए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक, संबंधित कंपनियों पर रेरा का कुल 77.66 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।

कई नोटिस के बाद भी जमा नहीं की रकम

जिला प्रशासन के अनुसार, बकाया वसूली के लिए संबंधित कंपनियों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद कंपनियों की ओर से निर्धारित रकम जमा नहीं कराई गई। प्रशासन ने वसूली के लिए लगातार दबाव बनाया और बकायेदारों को रकम जमा करने की चेतावनी भी दी थी।

इसके बाद गुरुवार को दादरी तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने तीनों निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया।

दफ्तर सील किए, अनाउंसमेंट कर दी थी चेतावनी

प्रशासन ने कार्रवाई से पहले भी संबंधित कंपनियों के कार्यालयों पर पहुंचकर बकाया वसूली की कोशिश की थी। टीम ने कार्यालयों के बाहर अनाउंसमेंट कर बकाया रकम जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा कंपनियों के दफ्तरों को कई बार सील भी किया गया था।

नोटिस, चेतावनी और कार्यालय सील किए जाने के बावजूद बकाया रकम जमा नहीं होने पर प्रशासन ने अब गिरफ्तारी की कार्रवाई की है।

एसडीएम के सामने पेश किए गए तीनों निदेशक

गिरफ्तारी के बाद तीनों निदेशकों को दादरी के एसडीएम के सामने पेश किया गया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बकाया रकम जमा नहीं करने और पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराने के आधार पर उन्हें अधिकतम 15 दिन की हिरासत में जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए।

डीएम मेधा रूपम के निर्देश पर कार्रवाई

जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकायेदारों के खिलाफ राजस्व वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि बकाया रकम जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई को रेरा के बकाये की वसूली के लिए प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। इससे उन बिल्डर कंपनियों को भी संदेश गया है, जिन पर लंबे समय से सरकारी बकाया लंबित है।

संपादकीय

सौ वर्षों की यात्रा में संघ की पहचान बना स्वयंसेवक का समर्पण



भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन अनेक विचारधाराओं, परंपराओं और संगठनों के योगदान से निर्मित हुआ है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक प्रगति, राजनीतिक व्यवस्था अथवा सैन्य क्षमता में नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों के चरित्र, सामाजिक एकता, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध में भी निहित होती है। इसी दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वर्ष 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के नेतृत्व में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। सौ वर्षों के बाद भी संघ की पहचान उसके स्वयंसेवकों के आचरण, संगठनात्मक अनुशासन और सेवा गतिविधियों से जुड़ी हुई है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह कथन कि सौ साल बाद भी स्वयंसेवक ही संघ की सबसे बड़ी पहचान हैं, संगठन की कार्यपद्धति को समझने का महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है।

संघ की स्थापना के पीछे मूल विचार व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का था। डॉ. हेडगेवार का मानना था कि समाज को संगठित और सशक्त बनाने के लिए ऐसे नागरिक तैयार होने चाहिए, जिनमें अनुशासन, आत्मविश्वास, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना हो। इसी उद्देश्य से दैनिक शाखा की परंपरा विकसित हुई। शाखा में शारीरिक गतिविधियों के साथ सामूहिकता, बौद्धिक चिंतन और सामाजिक व्यवहार का अभ्यास कराया जाता है। संघ की संगठनात्मक विशेषता यह रही है कि यहां पद अथवा प्रतिष्ठा की अपेक्षा स्वयंसेवक के दायित्व और उसके व्यवहार को महत्व दिया जाता है। मोहन भागवत ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के नवीनीकृत मुख्यालय में नवनिर्मित सभागार के उद्घाटन समारोह में संघ के शुरुआती दिनों से जुड़ा इब्राहिम नामक व्यक्ति का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि 1930 के दशक में सेंट्रल प्रोविंस की विधानसभा में संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी थी। उस समय संगठन को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन डॉ. हेडगेवार की व्यक्तिगत पहचान थी। ऐसे कठिन समय में इब्राहिम नाम के व्यक्ति ने संघ के पक्ष में आवाज उठाई थी। उनका तर्क था कि संघ को सांप्रदायिक संगठन मानकर बंद करना उचित नहीं है। वे डॉ. हेडगेवार को जानते थे और उन्हें अच्छा व्यक्ति मानते थे। इसलिए केवल वैचारिक धारणाओं के आधार पर संगठन को दोषी ठहराना उचित नहीं समझते थे। इब्राहिम का यह प्रसंग आज के सामाजिक वातावरण में विशेष महत्व रखता है। भारतीय समाज की खूबसूरती यह है कि यहां विचारों की भिन्नता के बावजूद एक-दूसरे के प्रति सम्मान और संवाद की परंपरा रही है। किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके धर्म, जाति अथवा राजनीतिक विचारों से नहीं होनी चाहिए। उसके व्यवहार, कार्य और सामाजिक योगदान को भी महत्व मिलना चाहिए। इब्राहिम ने जिस समय संघ के पक्ष में अपनी बात रखी, उस समय उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी संगठन के बारे में धारणा बनाने से पहले उसके वास्तविक स्वरूप और उसके लोगों को समझना आवश्यक है।

बिलॉन्गिंग : प्रेम, पहचान और एक स्त्री की यात्रा



महेन्द्र तिवारी
साहित्यकार एवं लेखक
पूर्व वायुसैनिक, नई दिल्ली

किसी व्यक्ति का जीवन केवल उसके जन्मस्थान, परिवार, भाषा और नागरिकता से नहीं पहचाना जाता। कई बार जीवन की सबसे बड़ी यात्रा अपनेपन की तलाश होती है। एक ऐसे देश में अपना घर तलाशना, जिसकी भाषा अलग हो, संस्कृति अलग हो और जीवन जीने के तौर-तरीके भी भिन्न हों, आसान नहीं होता। विशेषकर तब, जब वही व्यक्ति आगे चलकर उस देश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में शामिल हो जाए। सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging A Journey of Love' को इसी दृष्टिकोण से पढ़ना अधिक सार्थक होगा। यह केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व की जीवनगाथा नहीं, बल्कि प्रेम, पहचान, पारिवारिक संबंधों, त्रासदियों और एक नए देश को अपना बनाने की लंबी यात्रा का वृत्तांत भी है। हार्परकॉलिन्स इंडिया ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इससे पहले इसके प्रकाशन की जिम्मेदारी पेंगुइन इंडिया के पास थी, लेकिन संपादकीय मतभेदों के बाद प्रकाशक बदल गया। पुस्तक के प्रकाशन से जुड़ी यह घटना भी बताती है कि सोनिया गांधी का व्यक्तित्व और उनसे जुड़ी सामग्री साहित्यिक दुनिया के साथ-साथ राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श में भी कितनी दिलचस्पी पैदा करती है।

इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता इसका निजी स्वर है। सोनिया गांधी ने स्वीकार किया है कि अपने जीवन के बारे में लिखना उनके लिए सहज नहीं था। वर्षों से मन में संजोकर रखी स्मृतियों, अनुभवों और भावनाओं को सार्वजनिक करना उनके लिए एक कठिन प्रक्रिया रही। दरअसल, सोनिया गांधी दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहने के बावजूद अपने निजी जीवन को लेकर अपेक्षाकृत मौन रही हैं। उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, कहा गया और राजनीतिक बहसों में अनेक तरह की धारणाएँ बनाई गईं। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी कहानी अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया है। यही इस आत्मकथा को विशेष बनाता है। पुस्तक की शुरुआत युद्ध के बाद के इटली के वेनेटो क्षेत्र में बीते उनके बचपन से होती है। एक सामान्य इतालवी परिवार में पली-बढ़ी सोनिया माइनो की जीवनयात्रा उन्हें कैम्ब्रिज तक ले जाती है। वर्ष 1965 में वहीं उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। यह मुलाकात धीरे-धीरे प्रेम और फिर विवाह के रिश्ते में बदल गई। एक ऐसे भारतीय युवक से प्रेम, जिसके परिवार का संबंध भारत की राजनीति के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में था, सोनिया के जीवन को एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ।

भारत आना उनके लिए केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं था। यह एक नई भाषा, नई संस्कृति, नए सामाजिक परिवेश और नई पारिवारिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की शुरुआत थी। इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात, हिंदी सीखने के प्रयास, भारतीय परिधान के रूप में साड़ी को अपनाना और भारतीय खानपान तथा जीवनशैली से परिचित होना, ये सभी प्रसंग एक विदेशी युवती के धीरे-धीरे भारतीय परिवेश में रचने-बसने की कहानी कहते हैं। इन प्रसंगों में केवल एक परिवार की बहू बनने की कहानी नहीं, बल्कि अपनी पुरानी पहचान को साथ लेकर एक नई पहचान गढ़ने की प्रक्रिया दिखाई देती है।

लेकिन जीवन हमेशा प्रेम और अपनत्व की सहज राह पर नहीं चलता। गांधी परिवार को एक के बाद एक ऐसी त्रासदियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सोनिया गांधी के जीवन को भीतर तक प्रभावित किया। संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु, वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और फिर 1991 में राजीव गांधी की हत्या, ये घटनाएँ केवल राजनीतिक इतिहास की बड़ी घटनाएँ नहीं थीं। इनके पीछे एक परिवार का असहनीय दुख, एक पत्नी का अकेलापन और एक माँ की पीड़ा भी छिपी थी।

राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परिवार को संभालने और निजी जीवन को फिर से व्यवस्थित करने की थी। वे सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहती थीं। लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें बार-बार सार्वजनिक जीवन की ओर खींचा। इस आत्मकथा का एक महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि राजनीति में उनका प्रवेश किसी पूर्वनिर्धारित महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों, जिम्मेदारियों और पारिवारिक विरासत से जुड़ी घटनाओं की परिणति के रूप में सामने आता है।

पुस्तक का सबसे चर्चित प्रसंग वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने के निर्णय से जुड़ा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की चुनावी जीत के बाद सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की व्यापक चर्चा थी। लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया। पुस्तक में उनका दावा है कि वे चुनाव से कई महीने पहले ही इस संबंध में अपना निर्णय कर चुकी थीं। इस प्रसंग को कांग्रेस ने त्याग और नैतिक साहस के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि राजनीतिक विरोधियों ने इसे अलग-अलग नजरियों से देखा। किसी ने इसे राजनीतिक रणनीति कहा तो किसी ने परिस्थितियों की उपज माना। यहाँ पाठक को एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। आत्मकथा इतिहास की निष्पक्ष पाठ्यपुस्तक नहीं होती। यह लेखक की स्मृतियों, अनुभवों, मान्यताओं और दृष्टिकोणों से निर्मित जीवन का वृत्तांत होती है। इसलिए सोनिया गांधी द्वारा प्रस्तुत घटनाओं और उनके निष्कर्षों को उनके व्यक्तिगत पक्ष के रूप में समझना चाहिए, न कि प्रत्येक विवाद का अंतिम ऐतिहासिक निर्णय मान लेना चाहिए।

पुस्तक में वर्ष 1975 की आपातकालीन स्थिति, बाबरी मस्जिद विवाद, 1984 के सिख विरोधी दंगे, मनमोहन सिंह सरकार में उनकी भूमिका, प्रणब मुखर्जी की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, वर्ष 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस के समझौते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंधों जैसे विषयों का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। ये प्रसंग आत्मकथा को निजी स्मृतियों से आगे ले जाकर समकालीन भारतीय राजनीति के विमर्श से जोड़ते हैं। हालाँकि, इन विषयों को पढ़ते समय कुछ प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं। क्या पुस्तक में सभी विवादों पर समान विस्तार और स्पष्टता से बात की गई है? क्या कुछ ऐसे प्रसंग हैं, जिन पर लेखिका ने मौन रहना उचित समझा है? क्या राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या में व्यक्तिगत दृष्टिकोण कहीं तथ्यों पर हावी होता है? इन प्रश्नों का उत्तर तलाशने के लिए पाठक को अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों, समकालीन समाचारों और अलग-अलग विचारधाराओं से लिखी गई पुस्तकों का भी सहारा लेना चाहिए। किसी भी आत्मकथा की विश्वसनीयता उसके लेखक की ईमानदारी के साथ-साथ उसके कथन को दूसरे स्रोतों से परखने की हमारी क्षमता पर भी निर्भर करती है। इस पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पक्ष स्त्री की पहचान और उसके संघर्ष से जुड़ा है। एक इतालवी युवती, जो भारत की भाषा और राजनीतिक संस्कृति से अपरिचित थी, धीरे-धीरे भारतीय समाज का हिस्सा बनी और अंततः देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेताओं में शामिल हुई। यह यात्रा अपने आप में असाधारण है। इसमें एक स्त्री का प्रेम है, परिवार के प्रति समर्पण है, व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग है और परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए सार्वजनिक जीवन में अपनी जगह बनाने का अनुभव भी है। हालाँकि, इस यात्रा को केवल त्याग और समर्पण के चश्मे से देखना भी उचित नहीं होगा। सोनिया गांधी का राजनीतिक जीवन सत्ता, संगठन, निर्णय और जवाबदेही से भी जुड़ा रहा है। इसलिए उनकी आत्मकथा का मूल्यांकन करते समय निजी संवेदनाओं और सार्वजनिक जिम्मेदारियों, दोनों को ध्यान में रखना आवश्यक है। एक व्यक्ति के निजी दुख के प्रति संवेदनशील होना और उसके राजनीतिक निर्णयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, दोनों बातें एक साथ संभव हैं। मेरे विचार से 'Belonging' को दो समानांतर यात्राओं के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। पहली यात्रा प्रेम और अपनेपन की है, जिसमें सोनिया और राजीव का रिश्ता तथा सोनिया का भारत को अपना घर बनाने का अनुभव शामिल है। दूसरी यात्रा सत्ता और सार्वजनिक जीवन की है, जिसमें एक ऐसी महिला का राजनीतिक केंद्र तक पहुँचना शामिल है, जिसकी शुरुआती इच्छा राजनीति से दूर रहने की थी।

इस पुस्तक को पढ़ते समय न तो श्रद्धा का भाव इतना प्रबल होना चाहिए कि हर बात को निर्विवाद सत्य मान लिया जाए और न ही राजनीतिक विरोध इतना हावी होना चाहिए कि लेखिका के व्यक्तिगत अनुभवों को ही नकार दिया जाए। साहित्य और आत्मकथा का उद्देश्य केवल प्रशंसा या आलोचना करना नहीं, बल्कि मनुष्य और उसके समय को समझने की दृष्टि विकसित करना भी है। अंततः 'Belonging A Journey of Love' का महत्व इसी बात में है कि यह हमें एक ऐसे व्यक्तित्व के भीतर झाँकने का अवसर देती है, जिसे हमने अब तक अधिकतर राजनीतिक मंचों, सार्वजनिक वक्तव्यों और सत्ता के गलियारों में देखा है। यह पुस्तक कितनी ऐतिहासिक सच्चाइयों को सामने लाती है और कितने प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ती है, इसका निर्णय पाठक अपने अध्ययन और विवेक से करेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि किसी दूसरे देश से आई एक युवती का भारत के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाने और फिर इसी देश के राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने का सफर अपने आप में अध्ययन और विमर्श का विषय है। किसी देश को अपना मान लेना केवल उसकी नागरिकता स्वीकार कर लेना नहीं होता। उसके सुख-दुख, उसकी भाषा, उसकी स्मृतियों और उसके लोगों से भावनात्मक रिश्ता जोड़ना भी होता है। शायद इसी अर्थ में इस आत्मकथा का शीर्षक 'Belonging' सबसे अधिक अर्थपूर्ण हो उठता है। यह केवल भारत में रहने की कहानी नहीं, बल्कि भारत को अपना मानने और अपनेपन की पहचान खोजने की कहानी है। यही इसकी सबसे बड़ी साहित्यिक और मानवीय उपलब्धि है।

दिल्ली की जहरीली हवा से गहराता स्वास्थ्य संकट, प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम है प्रदूष

-कांतिलाल मांडोत-

देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या एक बार फिर गंभीर रूप धारण कर चुकी है। दीपावली के बाद वातावरण में बढ़ती धुंध और जहरीले प्रदूषक कणों ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हालात यह हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है। यह केवल राजधानी की समस्या नहीं है, बल्कि देश के पर्यावरणीय संतुलन पर मंडराते खतरे का संकेत है। दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित 50 शहरों में 49 शहरों का भारत में होना हमारी विकास व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक्यूआई का 821 तक पहुंचना इस संकट की व्यापकता को दर्शाता है।

दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ना अब हर वर्ष दोहराई जाने वाली समस्या बन गया है। सर्दियों की शुरुआत होते ही हवा की गुणवत्ता गिरने लगती है। दीपावली के दौरान आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं पहले से मौजूद प्रदूषण को और बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर दौड़ते लाखों वाहन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक इकाइयों का उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाना और आसपास के राज्यों में कृषि अवशेषों का प्रबंधन नहीं होना भी प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। मौसम में बदलाव और हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा रहने लगते हैं। यही कारण है कि राजधानी की हवा कुछ दिनों में ही सांस लेने के लिए चुनौती बन जाती है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि प्रदूषण का प्रभाव किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रहता। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पहले से सांस या हृदय संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोग इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। लगातार दूषित हवा में रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। आंखों में जलन, खांसी, सांस लेने में परेशानी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। गंभीर प्रदूषण का असर स्वस्थ व्यक्तियों पर भी पड़ सकता है। जिस हवा को जीवन का आधार माना जाता है, वही जब स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने लगे तो इसे सामान्य मौसमी परेशानी समझना बड़ी भूल होगी।

वायु गुणवत्ता सूचकांक के अलग-अलग स्तर प्रदूषण की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। 201 से 300 तक एक्यूआई खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर श्रेणी



में आता है। दिल्ली के कई इलाकों में गंभीर स्तर तक पहुंचना प्रशासन के लिए चेतावनी है। इसके साथ ही भोपाल, उज्जैन और हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंचने की जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, बुलंदशहर और गाजियाबाद जैसे शहरों में भी हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदूषण की समस्या केवल दिल्ली की भौगोलिक सीमा में कैद नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के राज्यों के पर्यावरण पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है।

दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों की भूमिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता भी महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकारों से वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर उठाए गए कदमों का विवरण मांगा है। साथ ही दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस से भी जवाब तलब किया गया है। विशेष रूप से निर्धारित आयु पूरी कर चुके और प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की आवाजाही रोकने, उनकी पहचान करने तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की व्यवस्था प्रभावी बनाने पर जानकारी मांगी गई है। न्यायालय की इस पहल से स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल मौसमी उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि यातायात और परिवहन व्यवस्था में भी सुधार आवश्यक है। राजधानी में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निजी गाड़ियों के साथ मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी प्रदूषण बढ़ाने में योगदान देती है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को सुविधाजनक और सुलभ बनाना जरूरी है। बस और मेट्रो सेवाओं का विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जैसे कदम प्रभावी साबित हो सकते हैं। केवल कागजों पर नियम बनाकर प्रदूषण पर नियंत्रण संभव नहीं है। इसके लिए नियमित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

प्रदूषण की समस्या का समाधान राज्यों के आपसी सहयोग के बिना संभव नहीं है। दिल्ली के आसपास स्थित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण जरूरी है, जिनसे हवा दूषित होती है। किसानों को पराली के उचित प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनें, तकनीकी सहायता और आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराना चाहिए। निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय अनिवार्य होने चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की नियमित जांच होनी चाहिए। सड़कों की सफाई, हरित क्षेत्रों का विस्तार और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को भी प्राथमिकता देनी होगी।

इस चुनौती से निपटने में आम नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। छोटी दूरी के लिए पैदल चलना, साइकिल का उपयोग करना और सार्वजनिक परिवहन अपनाना उपयोगी कदम हैं। घरों और आसपास कचरा जलाने से बचना चाहिए। अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना भी पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा है। नागरिकों को यह समझना होगा कि स्वच्छ वातावरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

भारत आज विकास और आधुनिकता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़े शहरों में उद्योग, परिवहन और निर्माण गतिविधियों का विस्तार जरूरी है, लेकिन विकास की कीमत नागरिकों के स्वास्थ्य और प्रकृति के संतुलन से नहीं चुकाई जा सकती। दिल्ली की प्रदूषित हवा हमें यह सोचने के लिए विवश करती है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कैसी धरती सौंपना चाहते हैं। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित पर्यावरण किसी विलासिता के साधन नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। अब समय आ गया है कि प्रदूषण नियंत्रण को केवल सर्दियों का अभियान न मानकर पूरे वर्ष चलने वाली प्राथमिकता बनाया जाए। सरकार, प्रशासन, उद्योग जगत और नागरिक समाज मिलकर जिम्मेदारी निभाएं, तभी दिल्ली सहित देश के शहरों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार मिल सकेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं स्तम्भकार है)

कैंसर की दवाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से मरीजों को मिली बडी राहत

-सौरभ वार्ष्णेय-

कैंसर का नाम सुनते ही किसी भी परिवार के सामने सबसे पहले जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाता है। यह ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज न केवल मरीज को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ता है, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक कमर भी तोड़ देता है। इलाज की लंबी प्रक्रिया, महंगी जांच, अस्पतालों का खर्च और जीवनरक्षक दवाओं की कीमतें पहले से परेशान परिवारों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होतीं। ऐसे में कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में भारी कटौती होना निश्चित रूप से लाखों मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन इस फैसले के पीछे छिपी सच्चाई देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और दवा कारोबार पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कैंसर की 137 दवाओं की कीमतें कम की गई हैं। दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1, 364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी की हैं। इनमें 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत से अधिक घटाए गए हैं। कुछ दवाओं की कीमतों में तो 96.45 प्रतिशत तक की कमी की गई है। अनुमान है कि इस कदम से मरीजों को सालाना करीब 3, 540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि अब तक कैंसर के इलाज के नाम पर आम आदमी की जेब पर कितना बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 22 सितंबर को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कैंसर की दवाओं की रिटेल कीमत और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच भारी अंतर पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत की टिप्पणी थी कि 2, 700 रुपये की दवा मरीज को 27, 000 रुपये में मिलना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है। न्यायालय की यह नाराजगी केवल दवाओं की कीमतों को लेकर नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल था, जिसमें गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों की मजबूरी को कारोबार और मुनाफे का अवसर बना लिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद 17 अक्टूबर को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर कंपनियों का ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत निर्धारित किया। इसी निर्णय के बाद कीमतों में कमी का रास्ता साफ हुआ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों ने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। समिति में देश के प्रमुख कैंसर विशेषज्ञों, चिकित्सकों, अस्पतालों के प्रतिनिधियों और



सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों और व्यापारिक मार्जिन को तर्कसंगत बनाना था।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जीवन बचाने वाली दवाओं के कारोबार में इतना अधिक मुनाफा कैसे संभव हुआ? क्या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज की विवशता का फायदा उठाना उचित है? दवा उद्योग का अपना आर्थिक पक्ष है। कंपनियों को अनुसंधान, उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, वितरण और नई दवाओं के विकास पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन इन सभी खर्चों के नाम पर ऐसी कीमतें वसूलना, जिन्हें आम आदमी वहन ही न कर सके, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। दवा कोई सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं है। यह किसी व्यक्ति के जीवन, उसके परिवार की उम्मीद और उसके भविष्य से जुड़ी होती है।

भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आज भी आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती है। संपन्न परिवार बेहतर अस्पतालों और महंगे उपचार का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के सामने अक्सर इलाज जारी रखने या घर की आर्थिक स्थिति बचाने के बीच कठिन चुनाव करने की नौबत आ जाती है। कई बार लोग जमीन, मकान और पुश्तैनी संपत्ति तक बेच देते हैं। कुछ परिवार कर्ज में डूब जाते हैं तो कुछ आर्थिक असमर्थता के कारण उपचार अधूरा छोडने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालात में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण केवल आर्थिक नीति का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनशीलता का प्रश्न है।

हालांकि, केवल कीमतें घटा देना ही पर्याप्त नहीं होगा। सरकार और संबंधित नियामक संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित कीमतों का लाभ वास्तव में मरीजों तक पहुंचे। दवा दुकानों, अस्पतालों और वितरकों के स्तर पर नियमित निगरानी होनी चाहिए। यदि कोई कंपनी या विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनी रहे और कीमतों पर नियंत्रण के नाम पर उनकी आपूर्ति प्रभावित न हो। विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई 137 दवाओं की सूची को समय-समय पर अपडेट करने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। कैंसर के उपचार में लगातार नई दवाएं और तकनीकें सामने आ रही हैं। इसलिए मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था भी समय और जरूरत के अनुसार विकसित होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई और प्रभावी दवाएं भी आम मरीजों की पहुंच से बाहर न हों। सरकारी अस्पतालों में कैंसर उपचार की सुविधाओं का विस्तार, जांच की सुलभता और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है।

दरअसल, किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे मरीजों के लिए दवाओं की कीमत कम होना महज एक आर्थिक राहत नहीं, बल्कि जीवन की उम्मीद को मजबूत करने वाला कदम है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने इस दिशा में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। लेकिन इस राहत को स्थायी व्यवस्था में बदलना सरकार, दवा कंपनियों और नियामक संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है।

जीवन बचाने वाली दवाएं मुनाफे का असीमित माध्यम नहीं बननी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य केवल कारोबार नहीं, बल्कि मानव जीवन की रक्षा होना चाहिए। कैंसर से लड़ रहे मरीजों को बीमारी से संघर्ष करना चाहिए, दवाओं की कीमतों और आर्थिक शोषण से नहीं। यही इस फैसले का वास्तविक संदेश और एक संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था की कसौटी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है)

सार समचार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माताजी स्व. काशी बाई जी को अर्पित की श्रद्धांजलि



अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर उनकी माताजी स्वर्गीय काशी बाई जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने इस दुख की घड़ी में अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

नहाय-खाय के साथ आज से शुरू होगा छठ पर्व

अनप्लग इंडिया

गुडगांव: पूर्वांचल क्षेत्रवासियों का सबसे बड़ा पर्व छठ आज शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस पर्व को मनाने के लिए पिछले कई दिनों से पूर्वांचल की संस्थाएं गुरुग्राम में तैयारियां में जुटी हैं। यहां रहने वाले पूर्वांचल के लाखों लोगों के साथ स्थानीय लोग और जिला प्रशासन भी इस त्यौहार को लेकर सहयोग कर रहे हैं। छठ पर्व पर गुरुग्राम में लाखों परिवारों द्वारा बड़े स्तर पर छठ पूजा की जाती है। जगह-जगह पर अस्थायी घाट बनाए गए हैं। इस बार छठ पूजा समितियों द्वारा पिछले साल के मुकाबले और भी बेहतर तैयारियां की गई हैं। बड़ा कार्यक्रम शीतला माता मंदिर पार्किंग क्षेत्र में होगा।

आज से शुरु हो जाएगा 4 दिवसीय पर्व

आज से शुरू होने वाले छठ पर्व को लेकर जहां समितियों ने घाटों पर विशेष प्रबंध किए हैं। आज शुक्रवार को पहले दिन नहाय-खाय के साथ यह पर्व शुरू होगा। हालांकि नहाय-खाय की प्रक्रिया श्रद्धालुओं द्वारा घर पर ही की जाएगी। दूसरे दिन शनिवार को खरना, रविवार को श्रद्धालु सायंकालीन और सोमवार को प्रातः कालीन सूर्य देव को अर्ध्य देंगे।

36 घंटे का होगा उपवास

खरना में श्रद्धालु दूध व गुड़ से बनी खीर खाकर व्रत रखेंगें। उनका यह उपवास 36 घंटे का होगा। भगवान भास्कर की आराधना के बाद सभी आपस में प्रसाद का वितरण भी करेंगे। संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा।

छठ पर्व के बारे में है यह धारणा–छठ पर्व के बारे में कहा जाता है कि पूर्वांचल और बिहार में अनिवार्य रूप से लोग छठ मनाते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घरों में एकत्रित होते हैं। छठ पर्व के बारे में यह धारणा है कि यह मुख्य रूप से बिहार मूल के लोगों का पर्व है। इसके पीछे कारण यह है कि इस पर्व की शुरुआत अंगराज कर्ण से शुरु हुई मानी जाती है। अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर है जो बिहार में है। अंग राज कर्ण के विषय में कथा है कि यह पाण्डवों की माता कुंती और सूर्यदेव की संतान हैं। कर्ण अपना आराध्य देव सूर्य देव को मानते थे। वह नियमपूर्वक कमर तक पानी में जाकर सूर्य देव की आराधना करते थे और उस समय जरुरतमंदों को दान भी देते था। माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी और सप्तमी के दिन कर्ण सूर्यदेव की विशेष पूजा किया करते थे।

बिग 5 ग्लोबल में भारत के 80 प्रतिष्ठान दिखाएंगे भारतीय निर्माण उद्योग की ताकत

अनप्लग इंडिया

गुडगांव: मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया (एमईएएसए) के तेजी से बढ़ते निर्माण और शहरी विकास बाजार में भारत अपनी विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। आगामी 23 से 26 नवंबर तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय बिग 5 ग्लोबल में देश के 80 प्रतिष्ठान हिस्सा लेंगे। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) भारत के अध्यक्ष पंकज चड्ढा का कहना है कि अरंका द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बुनियादी ढांचे, आवास और टिकाऊ भवन निर्माण समाधानों की बढ़ती मांग के चलते देश का निर्माण बाजार 2031 तक 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में यह अंतरराष्ट्रीय मंच भारतीय निर्माताओं को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने और नए व्यावसायिक अवसर तलाशने का बड़ा मौका देगा। उनका कहना है कि इस प्रदर्शनी में 60 से अधिक देशों के एक हजार 800 से ज्यादा प्रदर्शक अपने 55 हजार नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी है। भारतीय प्रदर्शकों की सूची में एस्ट्रल लिमिटेड, सीआरआई पंप्स, एक्वासब इंजीनियरिंग, जैनसन केबल्स इंडिया, शक्ति इरिगेशन, हिमालयन एडहेसिव्स और एचपी एडहेसिव्स जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, जो पंप, पाइपिंग, केबल और निर्माण सामग्री के क्षेत्र में देश की क्षमता दिखाएंगी। भारत और यूएई के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों से भारतीय कंपनियों को क्षेत्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच मिल रही है।आयोजन में भारी निर्माण, कंक्रीट, डिजिटल कंस्ट्रक्शन और सुविधा प्रबंधन से जुड़े सात समवर्ती कार्यक्रम भी होंगे। साथ ही, इम्पैक्ट ट्रेल पहल के माध्यम से कम कार्बन उत्सर्जन और टिकाऊ (सस्टेनेबल) निर्माण तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इच्छुक व्यवसाय और आगंतुक पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

धूमसपुर की फैक्ट्री में 3 श्रमिकों की मौत पर एआईयूटीयूसी ने जताया गहरा रोष

अनप्लग इंडिया

गुडगांव: जिले के गांव धूमसपुर स्थित संधार कंपनी में बुधवार दोपहर केमिकल टैंकर में उतरने से हुई 3 श्रमिकों की दर्दनाक मौत पर ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) की प्रदेश कमेटी ने गहरा दुख और कड़ा रोष व्यक्त किया है। कमेटी के अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने कहा कि यह हादसा एक बार फिर उजागर करता है कि फैक्ट्री प्रबंधन और मालिक मजदूरों को इंसान की जगह महज एक पुर्जा समझते हैं। यही कारण है कि बिना किसी सुरक्षा उपकरण और बचाव के उपायों के मजदूरों को सीधे केमिकल टैंकर में उतार दिया गया, जिससे उनकी जान चली गई। आए दिन विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा उपकरणों के अभाव में श्रमिक या तो बेमौत मारे जा रहे हैं या फिर अंगहीन हो रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन, हरियाणा के श्रम विभाग और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि न तो दोषी प्रबंधकों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाती है और न ही ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोका जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। एआईयूटीयूसी की राज्य कमेटी ने सरकार, प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन के इस रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए संगठन ने सरकार से मांग की है कि संबंधित कंपनी के मालिकों और प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए, साथ ही प्रत्येक मृतक के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए।

हरियाणा का किसान अपनी मेहनत और पसीने से देश के अन्न भंडार भरने में निभा रहा अहम भूमिका : नायब सिंह सैनी

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति और कृषि एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हरियाणा का किसान अपनी मेहनत और पसीने के बल पर देश के अन्न भंडार भरने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रदेश के किसानों ने कृषि क्षेत्र में अपनी मेहनत से हरियाणा को एक अलग पहचान दिलाई है। हरियाणा सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान, फसल की उचित कीमत, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य और फसल विविधीकरण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि किसान केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रहें, बल्कि आधुनिक तकनीक, नई फसलों और कृषि आधारित उद्योगों को अपनाकर अपनी आमदनी में वृद्धि करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कृषि सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मेहनती किसानों ने अपनी लगन और परिश्रम से न केवल हरियाणा को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाया, बल्कि देश के खाद्यान्न भंडार को भरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र



मोदी की सोच हमेशा किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे किसान को बीज, खाद और कृषि दवाइयों जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है और उसे छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि किसान पर खेती की लागत का बोझ कम हो और उसे अपनी उपज का उचित मूल्य मिले। इसी दिशा में केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर किसानों के हित में अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू कर रही हैं।

सिंचाई व्यवस्था के लिए निरंतर हो रहा काम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सिंचाई व्यवस्था के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत लगभग 2,000 तालाबों पर काम किया जा रहा है। नए तालाबों का निर्माण और पुराने तालाबों का पुनर्जीवन किया जा रहा है, ताकि वर्षा जल का संरक्षण हो और भूजल स्तर में सुधार लाया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार नहरों और ड्रेनों की मरम्मत, पुनर्वास एवं सुदृढ़ीकरण पर भी विशेष ध्यान दे रही है, ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग कृषि कार्यों में हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देने के लिए 100, 200 और 500 एकड़ के क्लस्टर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इन क्लस्टरों में बड़ी डिग्गियां बनाई जाएंगी, जिनमें लगभग एक महीने की आवश्यकता के अनुरूप पानी संग्रहित किया जा सकेगा। इन डिग्गियों से सोलर पंप के माध्यम से स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई और बेहतर पैदावार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

रेणुकाजी, किशाऊ और लखवार बांधों से हरियाणा को मिलेगा अतिरिक्त पानी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पांच राज्यों के बीच रेणुकाजी, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं को लेकर समझौता किया गया है। इन परियोजनाओं से प्राप्त होने वाला पानी हरियाणा सहित दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी उपलब्ध होगा। इन परियोजनाओं से भविष्य में जल उपलब्धता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि प्राकृतिक जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े।

प्रदेश में एमएसपी पर खरीद की गारंटी–मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की गारंटी दी है। प्रदेश सरकार किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना और धान जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों पर निर्भरता कम करना है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए मोरनी ब्लॉक में किसानों के साथ समझौता किया गया है, जिसके तहत बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले किसानों की उपज को खेत से ही खरीदने की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों की रुचि लगातार बढ़ रही है। पोर्टल पर 40 लाख से अधिक किसानों द्वारा लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में करीब 45 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायतों की कृषि योग्य भूमि तथा कृषि विभाग की जमीन को भी किसानों को 10 वर्ष की लीज पर प्राकृतिक खेती के लिए देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन महासंघ (हैफेड) को मंडियों में प्राकृतिक खेती से उत्पादित अनाज की खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। खरीद से पहले उपज का प्रयोगशाला में परीक्षण भी कराया जाएगा।

गेहूं की बिजाई के समय किसानों को सरकार तत्काल उपलब्ध कराए सिंचाई का पानी : सैलजा

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने सिंचाई के पानी की पर्याप्त उपलब्धता की मांग को लेकर फतेहाबाद में आंदोलन कर रहे सिरसा, हिसार और फतेहाबाद जिलों के किसानों की मांगों का समर्थन किया है। सांसद ने कहा कि प्रदेश के किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई जल और आम नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना केंद्र एवं राज्य सरकारों की बुनियादी जिम्मेदारी है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि इस समय गेहूं की बिजाई का महत्वपूर्ण सीजन चल रहा है। किसानों को अपने खेतों में बुवाई और फसलों की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन पानी की समस्या के कारण उन्हें धरने, प्रदर्शन और आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान बातचीत और ठोस प्रशासनिक कदमों के माध्यम से करना चाहिए।

सांसद ने कहाकि कुछ महीने पहले उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष हरियाणा की दीर्घकालीन जल समस्या के समाधान के लिए यमुना नदी को घग्गर नदी से जोड़ने की संभावनाओं का अध्ययन कराने का सुझाव रखा था। इस प्रस्ताव पर तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय प्रभाव, जल उपलब्धता और संबंधित राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ऐसी परियोजना व्यवहार्य पाई जाती है तो इससे हरियाणा के अनेक क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं।

कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें घोषणाओं और प्रचार पर अधिक ध्यान दे रही हैं, जबकि किसानों की बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। सांसद ने कहा कि किसानों को जुमलेबाजी नहीं, बल्कि खेतों तक पानी पहुंचाने वाली प्रभावी योजनाएं चाहिए।

सांसद ने मांग की कि राज्य सरकार नहरों में पानी की आपूर्ति का शेड्यूल किसानों की जरूरतों के अनुरूप निर्धारित करे, संबंधित किसान संगठनों से तत्काल बातचीत करे और गेहूं की बिजाई के दौरान सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित करे। साथ ही केंद्र सरकार यमुना-घग्गर जल संपर्क के सुझाव पर संबंधित विशेषज्ञों और राज्यों के साथ विचार-विमर्श शुरू करे।

पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए:

कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता, संवाद और समयबद्ध कार्रवाई से ही संभव है। किसानों को उनकी फसलों के लिए पानी और नागरिकों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

किताब के जरिए कांग्रेस कर रही लोगों को भ्रमित : विपुल गोयल

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने करनाल को स्वच्छता के क्षेत्र में अवॉर्ड मिलने को जनता, प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि 2027 के सर्वेक्षण में हरियाणा के और शहरों को इस सूची में लाना सरकार का लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण को सभी की साझा जिम्मेदारी बताते हुए 1984 के मुद्दे पर किताब के जरिए बयानबाजी करने को लेकर कांग्रेस को भी घेरा। सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा, 'केवल करनाल को स्वच्छता का अवॉर्ड मिलना वहां के लोगों के प्रयासों का परिणाम है। चाहे वहां के प्रशासनिक अधिकारी हों, सफाई कर्मचारी हों या करनाल की जनता, सभी ने सहयोग करके सामूहिक प्रयास से यह अवॉर्ड जीतने का काम किया है। मैं उन सभी को



बहुत-बहुत बधाई देता हूं।' उन्होंने कहा कि स्वच्छता मिशन, जो 2014 के बाद पीएम मोदी ने शुरू किया, उसके तहत पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है। हरियाणा में भी बड़ा परिवर्तन आया है और सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा कि जब 2027 का सर्वेक्षण हो, तो हरियाणा के कई शहर इस तरह के अवॉर्ड जीतें। हम इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ और उस पर कार्य भी कर रहे हैं।

विपुल गोयल ने कहा कि चाहे डोर-टू-डोर कलेक्शन की बात हो, चाहे सैनिटेशन के टेंडरों की बात हो या उनमें आमूलचूल परिवर्तन करके व्यवस्था को और बेहतर बनाने की बात हो अथवा लेगेसी वेस्ट के निस्तारण का विषय हो, इन सभी पर काम चल रहा है। पिछले कुछ समय में हमने काफी सुधार भी किए हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों को इसमें और बड़े सुधार देखने को मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण का मामला लगातार चर्चा में है। पंजाब में पराली जलाने का काम तो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा एनसीआर में चाहे ट्रैफिक प्रदूषण की बात हो या वायु गुणवत्ता की, सरकार सभी पहलुओं पर काम कर रही है। इसके लिए कई तरह के बदलाव किए गए हैं और निर्माण कार्यों पर भी आवश्यक रोक लगाने का काम किया गया है।

पटौदी में गैस सिलेंडरों से घटतौली का मामला, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने हेली मंडी गैस सर्विस पर मारा छापा

अनप्लग इंडिया

गुडगांव: पटौदी क्षेत्र के गांव छिल्लरकी में घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली का मामला सामने आने के बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने हेली मंडी स्थित मेसर्स हेली मंडी गैस सर्विस के विरुद्ध छापेमारी की। जांच के दौरान घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से गैस निकालकर उपभोक्ताओं को निर्धारित वजन से कम गैस वाले सिलेंडर सप्लाई किए जाने का मामला सामने आया है। इससे पहले ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस सिलेंडरों से भरे एक ऑटो को भी कब्जे में ले चुकी है। जानकारी के अनुसार, गांव छिल्लरकी निवासी चरणजीत सिंह ने ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक कराया था। जब डिलीवरी कर्मचारी सिलेंडर लेकर पहुंचा तो उपभोक्ता ने उसका वजन करवाया। वजन करने पर सिलेंडर का कुल वजन करीब 26 किलो कुछ ग्राम मिला। उपभोक्ता ने करीब चार किलो गैस कम होने का आरोप लगाया। इसके बाद गांव के सरपंच अशोक और अन्य ग्रामीणों ने ऑटो



में रखे दूसरे सिलेंडरों का भी वजन करवाया। ग्रामीणों के अनुसार, जांच में कुछ सिलेंडरों में दो से छह किलो तक गैस कम मिली। ऑटो में करीब 24-25 सिलेंडर रखे हुए थे।

मामले की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सिलेंडरों से भरे ऑटो को कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भी शिकायत देकर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

पहले भी मिल चुकी हैं शिकायतें–खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक (इंचार्ज सप्लाई) यक्ष तेवतिया ने बताया कि विभाग के संज्ञान में आया है कि उक्त गैस एजेंसी के खिलाफ पहले भी घटतौली और अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने और उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी के इस मामले को विभाग ने गंभीरता से लिया है। दोषी पाए जाने पर एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और संबंधित विभागीय नियमों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं से वजन जांचने की अपील–विभाग ने आमजन से अपील की है कि गैस सिलेंडर लेते समय उसकी सील और वजन की जांच अवश्य करें। यदि किसी उपभोक्ता को कम वजन, अधिक कीमत वसूली या अन्य अनियमितता की शिकायत मिलती है तो वह सीधे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि घटतौली और कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने की बैठक



अनप्लग इंडिया

करनाल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ खंड कुंजपुरा की मीटिंग पाल (गडरिया) धर्मशाला में हुई। अध्यक्षता खंड प्रधान रमेश कुमार ने की व संचालन खंड सचिव इंद्र पाल ने किया। विशेष रूप से जिला प्रधान बलराज सिंह, डा. रणदीप श्योराण, हुक्म सिंह राणा, राजपाल व गुरदयाल सिंह ने शिरकत की। सभा को राजपाल, रणदीप सिंह, हुक्म सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों की मांगों को लागू करवाने के लिए संघ लगातार आंदोलन कर रहा है। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के धरने प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। बलराज सिंह, मनोहर लाल व गुरदयाल सिंह ने कहा कि 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होगी। इसमें पेंशन वैलिडेशन बिल वापस करवाने, कम्यूटेशन 10 वर्ष 8 मास, 65, 70, 75 वर्ष आयु होने पर पांच प्रतिशत वृद्धि करने के मुद्दे उठाए जाएंगे। सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम, कार्पोरेशन मान्यता प्राप्त संस्थाओ के रिटायर्ड कर्मचारी पैंशन वित विधेयक वापस होने तक आंदोलन करते रहेंगे। संगठन मजबूती के लिए रिटायर्ड साथियों से मिलकर संगठन गतिविधियों की जानकारी देते हुए खंड के तीन सब जोन जैसे घीड़,बड़ा गांव,कुन्जपुरा बनाकर सब कमेटियों का गठन किया गया। इस अवसर पर सुरेश कुमार, हरदयाल सैनी, जगदीश, बलदेव सिंह, ज्ञान सिंह , सुखी राम, मामू राम, फूल सिंह , महावीर सिंह, कश्मीर सिंह,अमर सिंह, दिलबाग सिंह, पुन्नू राम, लाल चन्द, सुन्दर लाल, अत्तर सिंह, जोगिंदर सिंह, गुलाब सिंह कर्म चन्द, पूर्णचंद, नरेश, पालाराम, महेंद्र सिंह, रामपाल, राजकुमार, धर्मवीर व खुशी राम मौजूद रहे।

गुड़गांव में नशे पर लगाम लगाने को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

अनप्लग इंडिया

गुड़गांव। जिला में तेजी से फैलते नशे के कारोबार को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर्ल चौधरी के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शहर में नशे के अवैध नेटवर्क पर अंकुश लगाने, युवाओं को नशे के जाल से बचाने और स्कूल-कॉलेजों के आसपास सुरक्षा व पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान सूबे सिंह यादव एडवोकेट, सीमा हुड्डा, विकास हुड्डा, हरकेश प्रधान, राजीव यादव समेत आदि मौजूद रहे। पंकज डावर की अध्यक्षता में पुलिस आयुक्त सिबाश कबिराज को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कुछ समय से गुरुग्राम में नशे का अवैध कारोबार एक गंभीर सामाजिक एवं कानून-व्यवस्था की समस्या बनता जा रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं रिहायशी कॉलोनियों में नशीले पदार्थों की बिक्री और इनके अवैध नेटवर्क को लेकर आम नागरिकों में गहरी चिंता और भय का माहौल है। कांग्रेस



ने सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति युवा पीढ़ी को बताया है। ज्ञापन में कहा गया कि विशेषकर स्कूल और कॉलेजों में पढने वाले विद्यार्थी नशे के सौदागरों के निशाने पर हैं। यदि समय रहते इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो इसका दुष्परिणाम न केवल युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा, बल्कि पूरे समाज की सामाजिक संरचना प्रभावित होगी।

जिला कांग्रेस कमेटी (शहरी) ने पुलिस आयुक्त के समक्ष 7 प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग स्कूल एवं कॉलेजों के बाहर विशेष गश्त बढ़ाने की है। दूसरी मांग रिहायशी कॉलोनियों में सख्त कार्रवाई की है। तीसरी मांग नशा तस्करों के नेटवर्क पर प्रहार की है। चौथी मांग विशेष एंटी-ड्रग अभियान चलाने की है। पांचवीं मांग पीजी, हॉस्टल एवं किराये के मकानों की निगरानी की है। छठी मांग गुप्त शिकायत व्यवस्था बनाने की है। सातवीं मांग युवाओं के लिए जागरुकता अभियान चलाने की है। पंकज डावर ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों एवं सामुदायिक केंद्रों में नशे के दुष्परिणामों को लेकर जागरुकता अभियान चलाए जाएं तथा नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं के पुनर्वास के लिए भी प्रयास किए जाएं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को बर्बाद नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को तबाह कर देता है। जिस शहर की पहचान देश के प्रमुख औद्योगिक एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में होती है, वहां हमारी युवा पीढ़ी का नशे की गिरफ्त में जाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने मांग की कि इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से ठोस कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाए। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष पर्ल चौधरी ने कहा कि गुड़गांव की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने और शहर को नशामुक्त बनाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का कांग्रेस का उद्देश्य है। हम सब मिलकर नशे को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करेंगें। नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है।

संक्षिप्त डायरी

अखिलेश यादव पर ओमप्रकाश राजभर का तीखा हमला, बोले- छह दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला से मांगें माफी

अनप्लग इंडिया

चंदौली आजमगढ़ में ओमप्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि उन पर 'सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को' वाली कहावत सटीक बैठती है। कहा कि छह दिसंबर को अखिलेश अयोध्या जाकर रामलला से माफी मांगें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भिउरा स्थित सुभासपा कार्यालय पर गौड़ समाज की महिलाओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि उन पर 'सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को' वाली कहावत सटीक बैठती है। आरोप लगाया कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के बाद अब अखिलेश हिंदू मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी राजनीति 'न अली मिले न बजरंगबली' जैसी हो गई है। राजभर ने सलाह दी कि अखिलेश 12 तारीख के बजाय छह दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला के सामने सिर झुकाएं और माफी मांगें। सपा के यादव वोट बैंक में बिखराव का दावा करते हुए उन्होंने गोरखपुर एमएलसी चुनाव का हवाला दिया। कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को सपा उम्मीदवार से अधिक समर्थन मिला और पार्टी प्रत्याशी तीसरे स्थान पर पहुंच गया। आजमगढ़ मंडल में भी 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के कई यादव नेताओं के बगावत कर चुनाव लड़ने का दावा किया। शिवपाल और अखिलेश के रिश्तों पर उन्होंने कहा कि चाचा-भतीजे एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं। कारसेवकों पर गोलीबारी के मुद्दे पर सपा नेता पवन पांडेय की चुनौती का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव का लोकसभा और मुलायम सिंह यादव का विधानसभा में दिया गया बयान सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने पवन पांडेय को दोनों बयान पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि यदि वे अपनी बात पर कायम हैं तो राजनीति छोड़ दें।

बस चालक ने फंदा लगाकर दी जान, 20 दिन पहले ही पत्नी-बेटियों को मनाकर लाया था घर

अनप्लग इंडिया

कानपुर। नजीराबाद थाना क्षेत्र स्थित गुमटी नंबर पांच में बस चालक ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। नशे की लत के कारण चल रहे पारिवारिक तनाव के बीच वह 20 दिन पहले ही अपनी पत्नी और दो बेटियों को मायके से मनाकर घर लाया था। कानपुर में पत्नी और दो बेटियों को 20 दिन पहले ही मनाकर घर वापस लाने वाले शशिकांत दीक्षित उर्फ दीपू (40) ने बुधवार को फंदा लगाकर जान दे दी। नजीराबाद थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर पांच स्थित घर में पत्नी नौकरी पर गई थी। इसी दौरान उसने खुद को कमरे में बंद कर साड़ी के सहारे पंखे से फंदा लगा लिया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर बेटियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटे। पुलिस ने खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शशिकांत निजी बस चालक था। परिवार में पत्नी सुधा और दो बेटियां सानवी व काव्या हैं। परिजनों के मुताबिक, नशे की लत के चलते पति-पत्नी के बीच तनाव रहता था। इसी वजह से सुधा काफी समय से बेटियों के साथ मायके पनकी में रह रही थी और वहीं प्राइवेट नौकरी कर रही थी। शशिकांत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था करीब 20 दिन पहले शशिकांत ने अपनी गलती स्वीकार कर पत्नी बेटियों को मनाया था। इसके बाद तीनों उसके साथ रहने के लिए घर लौट आई थीं। बुधवार शाम सुधा नौकरी पर गई थी। इसी दौरान शशिकांत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर बेटियों ने शोर मचाया। उनकी आवाज सुनकर परिवार के लोग और पड़ोसी पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, तो शशिकांत फंदे से लटका मिला। उसे नीचे उतारा गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की भाभी स्नेहा अवस्थी ने बताया कि बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटे थे। नजीराबाद इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

दवा न सुई...कटोरे से दर्द की छुट्टी, तिब्बतन बाउल थैरेपी से ठीक हो रहे रोग, यह भी होते हैं फायदें

एजेंसी

कानपुर। सीएसजेएमयू के योग विभाग की ओपीडी में तिब्बतन बाउल थैरेपी के जरिए मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सात धातुओं से बने कटोरों की ध्वनि तरंगें बिना दवा या सुई के एंजाइटी, डिप्रेशन और पुराने शारीरिक दर्द में बड़ी राहत दे रही हैं। केस-1: रोगी शकुनलता का कहना है कि उनके शरीर में दर्द रहता था। कटोरे की आवाज से शरीर में झनझनाहट हुई। इससे बहुत आराम मिला। तनाव कम हो गया। केस-2: रोगी एके शुक्ला का कहना है कि इस थैरेपी से बहुत आराम मिला है। शरीर का दर्द दूर हो जाता है, दिमाग को सुकून मिलता है। दर्द दूर करने में दवा से अधिक थैरेपी कारगर है। तांबा समेत सात धातुओं से बने कटोरों की झंकार ऐसे दर्द को भी दूर कर दे रही है जिस पर दवाएं कारगर नहीं होतीं। साथ ही एंजाइटी, डिप्रेशन, गर्दन, कमर के दर्द में तिब्बतन बाउल थैरेपी राहत दिला रही है। दवाएं खाते-खाते ऊबे रोगियों को थैरेपी से दर्द में आराम मिल रहा है। छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के स्कूल ऑफ फिजिकल एजूकेशन के योग विभाग में यह थैरेपी दी जा रही है। नर्वस सिस्टम और न्यूरो ट्रांसमीटर से जुड़े रोगों में थैरेपी बड़ी कारगर है। खासतौर से पुराने हो चुके रोगों में इससे फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही मानसिक तनाव में इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। योग विभाग के समन्वयक डॉ. रामकिशोर ने बताया कि ओपीडी स्तर पर थैरेपी शुरू कर दी गई है। इसके विशेषज्ञ डॉ. मनीष कुमार ओपीडी में रोगियों को थैरेपी देते हैं। शरीर के स्ट्रेस हार्मोन को कम करती हैं आवाजें डॉ. कुमार ने बताया कि तिब्बतियन बाउल मेडिटेशन एक प्राचीन ध्यान की विधि है। अभी ओपीडी स्तर पर रोगी देखे जा रहे हैं। बाद में थैरेपी को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाउल से निकलने वाली आवाजें शरीर के स्ट्रेस हार्मोन को कम करती हैं। गहरे विश्राम की स्थिति में ले जाती हैं। इसके नियमित अभ्यास से दिमाग शांत होता है।

टेलर की दुकान में लगी आग, दुकान में रक्खे कपड़े जलकर हुते राख



हमीरपुर (सैय्यद बासित अखतर) मौदहा में आजाद टेलर की दुकान में लगी आग। मौदहा पुलिस ने बताया कि सुबह तड़के साढ़े पांच बजे करीब आग लगने की जानकारी मिलने पर गढ़ाई बाजार में आजाद टेलर पुत्र स्वतंत्र कुशवाहा निवासी गढ़ाई बाजार की कपड़े की दुकान में बिना देर किये पहुंचकर फायर सर्विस की मदद से आग पर काबू पाया गया। जबकि आग की वजह की जानकारी पर पता चला कि दुकान के पास मौजूद कूड़े के ढेर में आग लगी थी, जिसके बाद आग टेलर की दुकान तक पहुंच गई, जिसके चलते दुकान में रखे कपड़े जलकर राख हो गये। पुलिस ने बताया कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं मामले में पुलिस की तरफ से जरुरी कार्यवाही की जा रही है।

मवेशी को काटने के शक में वाहन जब्त करना गैरकानूनी, मुआवजा दे यूपी सरकार

अनप्लग इंडिया



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल संदेह या कोरे अनुमान के आधार पर किसी भी नागरिक का व्यावसायिक वाहन जब्त नहीं किया जा सकता। मवेशियों को वध (काटने) के लिए पश्चिम बंगाल ले जाने का कोई ठोस सबूत न मिलने पर कोर्ट ने मिजार्पुर पुलिस की जब्ती की कार्रवाई को पूरी तरह गैरकानूनी करार दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित वाहन मालिक को 15 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा अदा करे। क्या था पूरा मामला? यह पूरा विवाद 18 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था, जब मिजार्पुर पुलिस ने याचिकाकर्ता तेज प्रकाश के व्यावसायिक वाहन (डीसीएम आयशर) को रोका था। इस वाहन में दो बैल लदे हुए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने यह आरोप लगाते हुए वाहन को जब्त कर लिया कि इन बैलों को अवैध रूप से काटने के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले को उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए वाहन की जब्ती का आदेश पारित कर दिया था। प्रशासन की इस एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ वाहन मालिक तेज प्रकाश ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पशुओं को वध के लिए ले जाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता किए जाने की भी कोई पुष्टि नहीं हुई थी, फिर भी बिना किसी ठोस आधार के उनका रोजगार का साधन छीन लिया गया। ईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और कानूनी पहलू मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने पुलिस और प्रशासन के तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अधिकारियों के पास ऐसा कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं था, जिससे यह साबित हो सके कि वाहन में लदे दो बैलों को काटने के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। अदालत ने पुलिस की इस दलील पर भी कड़ी नाराजगी जताई कि मिजार्पुर की सीमा बिहार से सटी होने के कारण यह मान लिया गया कि पशुओं को बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। कोर्ट ने इसे 'महज एक कोरा अनुमान' बताते हुए कहा कि केवल भौगोलिक निकटता के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति जैन ने यह भी रेखांकित किया कि पुलिस ने न तो दोनों बैलों का किसी पशु चिकित्सक से चिकित्सकीय परीक्षण कराया और न ही वाहन से किसी प्रकार का गोमांस या गोवंश के अवशेष बरामद हुए। ऐसे में गोवध निवारण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। मुआवजा और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश हाईकोर्ट ने मिजार्पुर प्रशासन के जब्ती आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए वाहन को छोड़ने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि जब्त किया गया वाहन व्यावसायिक उपयोग का था और लंबे समय तक पुलिस थाने में खड़े रहने के कारण मालिक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए अदालत ने आदेश दिया कि 18 सितंबर 2023 (जब्ती की तारीख) से लेकर वाहन की वास्तविक रिहाई की तारीख तक, मालिक को 40 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मुआवजा दिया जाए, जो कुल मिलाकर 15 लाख रुपये से अधिक बैठता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को हुई मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक कठिनाई के लिए 25 हजार रुपये अतिरिक्त देने का भी आदेश दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता भी दी है

एसपी ने विंध्याचल थानाध्यक्ष को किया लाइन हाजिर, दो पुलिसकर्मी निलंबित



अनप्लग इंडिया

मिजार्पुर मिजार्पुर जिले में बालक का अपहरण करने के बाद हत्या करने के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में विंध्याचल थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। आरोपी ने किशोर की गला दबाकर हत्या की थी। विंध्याचल थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में सोमवार शाम बाइक सिखाने के बहाने 12 वर्षीय बालक का अपहरण और हत्या मामले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने विंध्याचल थानाध्यक्ष अजित सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही तीन थानाध्यक्षों का स्थानांतरण किया है। क्या है मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में बालक प्रिंस का अपहरण करने के बाद आरोपी पिंटू ने लालगंज थाना क्षेत्र के कुशियरा फाल के जंगल में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी की छानबीन में जुटी पुलिस ने कुशियारा फाल से मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी। पूछताछ के बाद पुलिस ने जंगल से बालक का शव बरामद किया। मामले में एसपी ने चौकी प्रभारी गैपुरा विजय शंकर राय व हल्का प्रभारी राघवेंद्र राय को निलंबित कर दिया। मामले में विंध्याचल थानाध्यक्ष अजीत सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा जिगना

नेयवेली पावर प्लांट की बढ़ेगी क्षमता, लगेगी 660 MW की चौथी यूनिट, कैबिनेट मंत्री ने की समीक्षा बैठक

अनप्लग इंडिया



कानपुर । घाटमपुर स्थित नेयवेली पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए अब चौथी यूनिट लगाई जाएगी, जिसका कंपनी बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है। प्लांट के निरीक्षण और समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने विस्थापितों को योग्यतानुसार नौकरी देने के निर्देश कानपुर में घाटमपुर स्थित नेयवेली पावर प्लांट में अब चौथी यूनिट भी लगेगी। कंपनी बोर्ड ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है। यह बात प्लांट के अधिकारियों ने बुधवार को प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से कही। मालूम हो कि पूर्व योजना के तहत मौजूदा समय प्लांट में 660-660 मेगावाट की तीन यूनिट से 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही हैं। 660 मेगावाट की चौथी यूनिट लगने से प्लांट की क्षमता और बढ़ जाएगी। निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके परियोजना की वर्तमान स्थिति, विद्युत उत्पादन, संयंत्र की संचालन व्यवस्था तथा विभिन्न कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद परियोजना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में अधिकारियों ने परियोजना की प्रगति, तकनीकी व्यवस्थाओं, विद्युत उत्पादन की स्थिति तथा संयंत्र के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी।
चौथी यूनिट लगने से प्लांट की क्षमता और बढ़ जाएगी बैठक के दौरान परियोजना की उपलब्धियों, वर्तमान चुनौतियों और आगामी कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही संयंत्र की कार्यक्षमता बढ़ाने, बेहतर संचालन सुनिश्चित करने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर विशेष बल दिया गया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि चौथी यूनिट लगने से प्लांट की क्षमता और बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की भूमि प्लांट में गई है, उन लोगों को योग्यता के अनुसार नौकरी देने के लिए भी प्लांट के अधिकारियों से कहा है। नेयवेली के डीजीएम कौशिक भार ने बताया कि चौथी यूनिट स्थापित करने के लिए कंपनी द्वारा सैद्धांतिक प्रस्ताव पास हो गया है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी।

दिवाली के बाद पिछले साल से 58% ज्यादा प्रदूषित हुई काशी की हवा

अनप्लग इंडिया

वाराणसी वाराणसी में प्रदूषण का स्तर पिछली दिवाली से ज्यादा इस बार रहा। पिछले साल दिवाली से अगले तीन दिनों तक शहर का घटा था, लेकिन इस बार प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा। दिवाली पर आतिशबाजी का असर इस बार काशी की आबोहवा पर पिछले साल की तुलना में अधिक दिखाई दिया। पिछले साल दिवाली से अगले तीन दिनों तक शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार घटा था, लेकिन इस बार प्रदूषण का स्तर 58 प्रतिशत से अधिक बना रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दिवाली से अगले तीन दिन तक शहर का एक्यूआई 118 से घटकर 106 तक पहुंच गया था। इस बार दिवाली के दिन 224 दर्ज किया गया, जो अगले दिन बढ़कर 274 तक पहुंच गया। इसके बाद गिरावट शुरू हुई, लेकिन तीन दिन बाद भी एक्यूआई 134 रहा। पिछले साल 20 अक्तूबर को दिवाली थी। उस दिन एक्यूआई 118 दर्ज किया गया था। 21 अक्तूबर को बढ़कर 156 हो गया। 22 अक्तूबर को 121 और 23 अक्तूबर को घटकर 106 पर आ गया था। दिवाली के बाद तीसरे दिन तक हवा की गुणवत्ता में सुधार हो गया था। इस बार 8 नवंबर को दिवाली के दिन एक्यूआई 224 रहा। 9 नवंबर को 50 अंकों की और बढ़ोतरी हुई और यह 274 पहुंच गया। 10 नवंबर को गिरकर 160 और 11 नवंबर को 134 दर्ज किया गया। दिवाली के तीन दिन बाद भी एक्यूआई पिछले साल के मुकाबले 28 अंक अधिक रहा। चार दिनों के औसत की तुलना करें तो इस बार लगभग 58 फीसदी अधिक रहा। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के पीछे आतिशबाजी ही मुख्य कारण है। पिछले साल दिवाली के अगले दिन एक्यूआई में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार दो दिनों तक गिरावट दर्ज की गई। इस बार भी 9 नवंबर के बाद प्रदूषण कम होना शुरू हुआ, लेकिन चार दिनों के तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि हवा की गुणवत्ता पिछले साल के मुकाबले खराब रही। हालांकि, 11 नवंबर को एक्यूआई घटकर 134 पर आने से सुधार के संकेत मिले हैं। दिवाली पर आतिशबाजी के कारण शहर का एक्यूआई खराब हुआ था। हालांकि, इस बुधवार से थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है।

पंजाब से बिहार ले जा रहे थे 18 गोवंश, पुलिस मुठभेड़ में तीन तस्कर गिरफ्तार

अनप्लग इंडिया



गाजीपुर गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पंजाब से बिहार जा रहे 18 गोवंश बरामद किए गए। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के बाएं पैर में गोली लगी। पंजाब से गोवंश लादकर बिहार ले जा रहे तस्करों को भांवरकोल पुलिस ने मुहम्मदाबाद-भरौली मार्ग पर रसूलपुर के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में तीन तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के बाएं पैर में गोली लग गई। दोनों डीसीएम में नौ-नौ गोवंश लदे थे। पुलिस ने मौके से दो डीसीएम के साथ एक तमंचा, एक खोखा और एक कारतूस बरामद किया। क्या है पूरा मामला भांवरकोल थानाध्यक्ष राजीव पांडेय ने बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पंजाब से पशुओं को लेकर दो डीसीएम बिहार जा रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने रसूलपुर गांव के पास घेराबंदी कर एक डीसीएम को रोक लिया। तलाशी में उसमें नौ गोवंश मिले। चालक से पूछताछ में पता चला कि पीछे से एक और डीसीएम आ रही है, जिसमें नौ मवेशी लदे हैं। कुछ देर बाद दूसरा डीसीएम मौके पर पहुंचा तो पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से निशाना लगाकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल की पहचान पंजाब के लुधियाना जिले के समराला थाना क्षेत्र के हिम्मतनगर वार्ड नंबर आठ निवासी सुखदीप कुमार के रूप में हुई। वहीं, गिरफ्तार अन्य तस्करों की पहचान लुधियाना जिले के सदर जगरांव थाना क्षेत्र के चौकीमान निवासी दर्शन सिंह और समराला थाना क्षेत्र के बलियोन गांव निवासी पवन कुमार के रूप में हुई। घायल तस्कर का उपचार मुहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पंजाब से गोवंश लादकर बिहार में बेचने के लिए ले जा रहे थे।

काशी में 70 घाटों पर अब भी आठ हजार टन सिल्ट, व्रतियों की बढ़ेगी परेशानी

अनप्लग इंडिया



वाराणसी वाराणसी में छठ पर्व की तैयारियां अधूरी हैं। गंगा घाटों की पड़ताल में सामने आया कि इस बार व्रतियों को सिल्ट, सीवर, अंधेरे और गंदगी के बीच छठ पूजा करनी पड़ सकती है। इसकी वजह है नगर निगम की सफाई की धीमी रफ्तार। छठ महापर्व कल यानी 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। लेकिन गंगा के 70 से ज्यादा घाटों पर अब भी आठ हजार टन से ज्यादा सिल्ट जमा है। ऐसे में इतने कम समय में गंगा के 84 घाटों पर मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करना नगर निगम प्रशासन के लिए चुनौती है। बुधवार को गंगा घाटों की पड़ताल में सामने आया कि इस बार व्रतियों को सिल्ट, सीवर, अंधेरे और गंदगी के बीच छठ पूजा करनी पड़ सकती है। घाटों पर पर्याप्त सफाई के साथ शौचालय, चेंजिंग रूम और प्रकाश की व्यवस्था जरूरी है, लेकिन कई जगह ये सुविधाएं नदारद हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद कुछ घाटों पर पंप लगाकर सिल्ट हटाई जा रही है। नगर निगम की सफाई की धीमी रफ्तार के कारण कई घाटों की पांच से सात निचली सीढ़ियां अब भी सिल्ट में डूबी हैं। दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद घाट, मीर घाट, गाय घाट, दरभंगा घाट, तेलियानाला घाट और भैंसासुर घाट पर सिल्ट जमा है। इसी तरह प्रमुख अस्सी घाट, रविदास घाट, तुलसी घाट, भदैनी घाट, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट और मुंशी घाट पर भी सिल्ट और गंदगी फैली है। नगर निगम की ओर से सफाई कराई जा रही है, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए काम पूरा होने में कम से कम एक सप्ताह लग सकता है। पांच से ज्यादा घाटों पर सीधे गंगा में गिर रहा सीवर पड़ताल के दौरान मीर घाट, बुंदी परकोटा, सक्का घाट, हनुमानगढ़ी और मानसरोवर घाट पर गंदगी सीधे गंगा में जाती दिखाई दी। वहीं, अन्य घाटों की निचली सतह पर भी गंदगी मिली। पंचगंगा घाट और ललिता घाट के सामने गंगा में भी गंदगी तैरती नजर आई। 10 से ज्यादा घाटों पर कपड़े और कूड़े के गट्ठर घाटों की सफाई अभी पूरी नहीं हुई है। जल पुलिस चौकी के नीचे, शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट और केदार घाट समेत कई जगह कपड़ों के गट्ठर पड़े मिले। पांच घाटों पर ही सफाई करते दिखे कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद घाट, ललिता घाट, ब्रह्मा घाट और अस्सी घाट पर ही कर्मचारी मशीनों से सफाई करते दिखे।

तेज रफ्तार का कहर: मिजार्पुर में कार ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर मौत; नाराज ग्रामीणों ने लगाया जाम

अनप्लग इंडिया

मिजार्पुर मिजार्पुर में दर्दनाक हादसा हुआ। चील्ह थाना क्षेत्र के सागरपुर में एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मिजार्पुर जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के सागरपुर में बृहस्पतिवार सुबह तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और जाम समाप्त कराया। क्या है पूरा मामला जालू यादव बुधवार सुबह 11 बजे साइकिल से पुरजागीर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान औराई की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में जालू यादव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर रखकर आवागमन बाधित कर दिया। सूचना पर थाना प्रभारी चील्ह ब्रह्मदीन पांडेय और टेढ़वा चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने चालक को ग्रामीणों से छुड़ाकर हिरासत में लिया और समझा-बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनवाने और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पांडेय ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

कुमामोटो मास्टर्स : लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह



जापान, एजेंसी। कुमामोटो मास्टर्स जापान 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में अपने-अपने मुकाबले जीतकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य ने चीनी ताइपे के खिलाड़ी को सीधे गेम में हराया, जबकि पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 श्रीकांत ने डेनमार्क के खिलाड़ी के खिलाफ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की।

लक्ष्य सेन ने सीधे गेम में दर्ज की शानदार जीत

भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने कुमामोटो प्रीफेक्चरल जिम्नेजियम में खेले गए मुकाबले में चीनी ताइपे के ची यू जेन को 21-19, 21-18 से हराया। यह मुकाबला 49 मिनट तक चला, जिसमें लक्ष्य ने दोनों गेम में शानदार खेल दिखाया। लक्ष्य ने दबाव के बावजूद अपना संयम बनाए रखा और लगातार दो गेम जीतकर अगले दौर में जगह पक्की की। उनकी इस जीत से टूर्नामेंट में भारतीय उम्मीदों को मजबूती मिली है।

किदांबी श्रीकांत ने वापसी कर जीता मुकाबला

पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 किदांबी श्रीकांत ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया। हालांकि, उनका मुकाबला आसान नहीं रहा। डेनमार्क के रासमस गेमके ने पहला गेम 21-18 से जीतकर श्रीकांत पर दबाव बना दिया था। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने जोरदार वापसी की और दूसरा गेम 21-16 से अपने नाम किया। निर्णायक तीसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन श्रीकांत ने 24-22 से गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह मैच कुल 1 घंटे 8 मिनट तक चला।

BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स की रेस में लक्ष्य सेन की नजरें

लक्ष्य सेन के लिए यह टूर्नामेंट काफी अहम है। हाल ही में हायलो ओपन का खिताब जीतने के बाद उन्होंने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स की रेस में आठ स्थान की छलांग लगाई और 10वें नंबर पर पहुंच गए। अब लक्ष्य की नजरें टॉप-8 में जगह बनाने पर हैं, ताकि वह सीजन के आखिर में होने वाले BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकें। यह टूर्नामेंट चीन में 9 से 13 दिसंबर तक आयोजित होना है।

मिक्स्ड डबल्स में भारतीय जोड़ियों को मिली हार

पुरुष सिंगल्स में भारत को सफलता मिली, लेकिन मिक्स्ड डबल्स में भारतीय जोड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ध्रुव रावत और मनीषा के की जोड़ी को चीनी ताइपे की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी ये होंग वेई और निकोल गोंजालेस चान के खिलाफ 21-16, 14-21, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा।

वहीं, तनिषा क्रास्टो और हरिहरन अमसाकरुणन की जोड़ी भी मुकाबला नहीं जीत सकी। उन्हें चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी जियांग झेनबांग और वेई याशिन ने 21-7, 21-9 से सीधे गेम में हराया।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे एकदिवसीय में जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम

माउंट मौनगानुई , एजेंसी। भारतीय टीम यहां मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले चौथे एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबले में जीत के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 से आगे हैं। ऐसे में उसका लक्ष्य इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना रहेगा। इस मैच में उतरते ही भारतीय टीम बदली-बदली नजर आयेगी। इस अहम मैच में युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पहली बार एकदिवसीय प्रारुप में भारतीय टीम की कप्तानी करते दिखेंगे। वहीं 19 नवंबर से होने वाली टेस्ट सीरीज को देखते हुए नियमित कप्तान शुभमन गिल , केएल राहुल, सहित कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। ऐसे में ईशान किशन टीम में विकेटकीपर की मुख्य भूमिका भी निभाएंगे। इसके अलावा युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र और तेज गेंदबाज यश ठाकुर को अंतिम दो मैचों के लिए दल में शामिल किया गया है। वहीं, औकिब नबी को भी



बरकरार रखा गया है। अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी दोनो मैचों में बने रहेंगे।

वहीं, न्यूजीलैंड भी अपने घरेलू मैदान और हालातों का लाभ उठाकर भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देना चाहेगा। यह मुकाबला दोनों देशों के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली टीम आखिरी दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज को बराबरी पर समाप्त करना चाहेगी। इससे पहले उन्होंने टीम में बदलाव किए हैं। इसके तहत ही ब्रेट रैंडेल को न्यूजीलैंड ने चौथे और पांचवें एकदिवसीय मैच के लिए अपनी टीम के साथ जोड़ा है। 31 वर्षीय इस गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर टीम में जगह बनाई है। उन्होंने अब तक 55 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिसमें 100 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने चार बार 5 विकेट भी लिए हैं। इस तेज गेंदबाज के भारत के खिलाफ इस सीरीज में डेब्यू करने की उम्मीद है।

टीम इस प्रकार है

भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), आकिब नबी डार, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड टीम- मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, विल यंग, माइकल ब्रेसवेल, निक कैली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिचेल हे (विकेटकीपर), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, मैट हेनरी और काइल जैमीसन।

अंडर-19 एशिया कप: भारत ने अफगानिस्तान को आठ विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया



- लक्ष, आर्यवीर और विनीन ने लगाय अर्धशतक

अल अमरात , एजेंसी । कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी, आर्यवीर सहवाग और वीके विनीत के अच्छे प्रदर्शन से भारतीय टीम ने अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को आठ विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 228 रनों का लक्ष्य दिया था। जिसे भारतीय टीम ने केवल 36.5 ओवरों में ही केवल दो विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारतीय टीम की ओर से सबसे अधिक 93 रन लक्ष्य ने बनाये। इसके अलावा आर्यवीर और विनीत ने भी अर्धशतक लगाये।

इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए। उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, जहां अब्दुल्लाह नादरजान 14 और फरीदुल्लाह एहसास 13 रन ही बना पाये। हालांकि, सुभान जखैल ने 31 रन की पारी खेलकर पारी को संभालने की कोशिश की। बाद में, नुमान सालारजई और शाह फैसल रहीमी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51-51 रनों की अर्धशतकीय पारियां खेलीं। कप्तान सोहेल खान 36 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे टीम 227 रन बनाने में सफल रही। भारतीय गेंदबाजों में ईशान सूद सबसे सफल रहे, जिन्होंने अपने नौ ओवर में 43 रन देकर तीन विकेट लिए। आर्यन सावसानी ने दो विकेट लिए, जबकि काव्या पटेल, यशवर्धन चौहान और अर्जुन राजपूत को एक-एक सफलता मिली।

इसके बाद जीत के लिए मिले 228 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और आर्यवीर सहवाग ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 117 रनों की शानदार साझेदारी की। आर्यवीर सहवाग ने 57 गेंदों में 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद, लक्ष्य ने वीके विनीत के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने 90 गेंदों में 93 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल रहा। वह अपने शतक से मात्र सात रन से चूक गए और टीम के 194 रन के स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद, वीके विनीत ने 62 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल था। यशवर्धन चौहान ने भी 14 गेंदों में तेज 16 रन बनाकर नाबाद रहे, और भारत ने 36.5 ओवर में 230 रन बनाकर मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया।

इस बड़ी जीत के साथ भारतीय टीम ने अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पहुंच गयी है जहां अब उसका मुकाबला पहले सेमीफाइल की विजेता पाकिस्तान से होगा। खिताबी शनिवार, 14 नवंबर को अल अमरात में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा

आईपीएल2027: हार्दिक को लंबे समय तक पंजाब किंग्स के साथ रखना चाहते हैं: नेस वाडिया

लखनऊ , एजेंसी । नई दिल्ली- आईपीएल 2027 से पहले पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव करते हुए मुंबई इंडियंस से स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को ट्रेड कर लिया है। पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया ने हार्दिक को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा है कि फ्रेंचाइजी हार्दिक को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखना चाहती है। साथ ही उन्हें भरोसा है कि पंजाब की टीम में फैंस को हार्दिक का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा।

हार्दिक को लेकर नेस वाडिया का बड़ा बयान

नेस वाडिया ने हार्दिक पंड्या के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों इस साझेदारी को लेकर गंभीर हैं। उनके मुताबिक, हार्दिक पंजाब किंग्स के साथ जुड़ने को लेकर काफी उत्साहित हैं और टीम को अपना अनुभव देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पीटीआई से कहा, 'हम दोनों इस साझेदारी को लेकर बेहद गंभीर हैं। मेरी हार्दिक से अच्छी बातचीत हुई है। वह पूरी तरह से तैयार हैं और मेरा मानना है कि यहां आपको एक अलग तरह के हार्दिक पंड्या देखने को मिलेंगे।'

पंजाब किंग्स को हार्दिक से क्या उम्मीदें?

नेस वाडिया का मानना है कि हार्दिक पंड्या का अनुभव पंजाब किंग्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी के अलावा मैदान पर अपने अनुभव से भी टीम को मजबूती देंगे। वाडिया के मुताबिक, हार्दिक का जुड़ना सिर्फ खिलाड़ियों की अदला-बदली नहीं, बल्कि टीम को खिताब जिताने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा, 'वह अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने को लेकर बेहद उत्सुक



हैं। इससे हमारी टीम को मजबूती मिलेगी तथा मैदान पर श्रेयस और मैदान के बाहर रिकी (मुख्य कोच रिकी पोंटिंग) और सभी को काफी मदद मिलेगी।'

क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलेंगे हार्दिक?

हार्दिक पंड्या पहले गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए टीम को आईपीएल चैंपियन बना चुके हैं। ऐसे में उनके पंजाब किंग्स में आने के बाद कप्तानी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई थीं। हालांकि नेस वाडिया ने स्पष्ट किया कि हार्दिक को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने में कोई परेशानी नहीं होगी।

नेस वाडिया ने कहा, 'श्रेयस के हार्दिक के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। रिकी ने भी पहले हार्दिक के साथ काम किया है। यह हम सभी के लिए फायदेमंद है। हमारा मानना था कि हमें चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है और इसलिए हमें हार्दिक को टीम से जोड़ना अच्छा सौदा लगा।'

निशानेबाज नीरज ने विश्व चैंपियनशिप में जीता कांस्य, 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए कोटा मिला

नई दिल्ली , एजेंसी। भारतीय निशानेबाज नीरज कुमार ने बुधवार को दोहा में हुए आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नीरज ने अपने इस प्रदर्शन के साथ ही भारत ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए अपना दूसरा कोटा स्थान भी सुनिश्चित कर लिया है। यह उपलब्धि भारतीय निशानेबाजी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

फाइनल मुकाबले में नीरज ने कुल 346.5 अंक हासिल किए। वह रजत पदक जीतने की दौड़ में शामिले थे पर अंतिम दौर में 9.4 अंक के एक मामूली निशाने के कारण वह दूसरे स्थान से खिसक गये और उन्हें कांस्य पदक ही मिला। बावजूद इसके, उनका यह प्रदर्शन भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे भारत को आगामी ओलंपिक खेलों में भागीदारी के लिए एक और कोटा स्थान मिल गया।

इससे पहले, भारतीय निशानेबाज जयपाल मालवीय ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया था। नीरज की इस सफलता से अब भारत के खाते में दो ओलंपिक कोटा हो गए हैं, जो भारतीय निशानेबाजी के लिए एक सकारात्मक संकेत है और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए उत्साहजनक माहौल बनाता है। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक व्यक्तिगत तटस्थ खिलाड़ी दिमित्री पिमेनोव ने जीता, जिन्होंने फाइनल में प्रभावशाली 362.8 अंक हासिल करते हुए नया विश्व जूनियर रिकॉर्ड भी स्थापित किया। पिमेनोव ने भी अपने प्रदर्शन के दम पर लॉस एंजिलिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। वहीं स्लोवाकिया के निशानेबाज पैट्रिक जानी ने शानदार निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया और वे भी ओलंपिक कोटा प्राप्त करने में सफल रहे। भारत के ही एक अन्य निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भी इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे थे पर वह पदक जीतने में असफल रहे और 323.7 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहे।



अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम, 12 नवंबर से नई कीमतें होंगी लागू



नई दिल्ली । देश की प्रमुख डेयरी कंपनी 'अमूल' ने ताजा दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) ने बताया कि 12 नवंबर 2026 से देशभर में अमूल के प्रमुख दूध उत्पादों की कीमतों में लगभग 4 से 5 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी।

फेडरेशन के अनुसार, सबसे अधिक बिकने वाले अमूल ताजा टोंड दूध (3 प्रतिशत फैट) की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जो लगभग 3.3 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं अमूल गोल्ड दूध (6 प्रतिशत फैट) के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, जो करीब 5.5 प्रतिशत की वृद्धि है।

अमूल ने कहा कि दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग की लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

कंपनी के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में हरे और सूखे चारे, पशु आहार में इस्तेमाल होने वाले तेल खली (ऑयल केक), मक्का, शीरा (मोलासेस), दूध पैकेजिंग फिल्म और ईंधन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अमूल ने बताया कि गुजरात सहित देश के कई हिस्सों में कम और असमान बारिश के कारण डेयरी किसानों को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में उत्पादकों को बेहतर भुगतान देने और उनका समर्थन करने के लिए दूध की उपभोक्ता कीमतों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। फेडरेशन के अनुसार, अमूल से जुड़े सदस्य दुग्ध संघों ने पिछले एक साल में किसानों को दिए जाने वाले दूध खरीद मूल्य में 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि की है। ताजा मूल्य संशोधन से किसानों को और बेहतर भुगतान मिल सकेगा। अमूल ने कहा कि सहकारी ढांचे के तहत उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राजस्व का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा उसके 36 लाख दुग्ध उत्पादक किसानों को वापस दिया जाता है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि दूध की बिक्री कीमत में हुई बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा सीधे किसानों तक पहुंचेगा, जिससे उन्हें अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

डब्ल्यूटीए फाइनल्स : सबालेंका को हराकर मीरा एंड्रीवा सेमीफाइनल में पहुंची

ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की पांचवीं खिलाड़ी बनी

इंडियन वेल्स , एजेंसी । रुस की महिला टेनिस स्टार मीरा एंड्रीवा ने बेलारुस की एरिना सबालेंका को हराकर पहली बार डब्ल्यूटीए फाइनल्स में प्रवेश किया है। इस रोमांचक मुकाबले में एंड्रीवा ने सबालेंका को सीधे सेटों में 6-4, 6-0 से पराजित किया। एक घंटे से कुछ अधिक समय तक चले इस मुकाबले में एंड्रीवा ने अंतिम 11 गेम जीतकर 55 में से 45 अंक हासिल किए। इस जीत के साथ ही वह 2009 में कैरोलिन वोज्नियाकी के बाद डब्ल्यूटीए फाइनल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। वह साल 2003 में मौजूदा राउंड-रॉबिन फॉर्मेट शुरू होने के बाद से सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पांचवीं कम उम्र की पांचवीं खिलाड़ी हैं। उनसे पहले मारिया शारापोवा, एना इवानोविच, वोज्नियाकी और कोको गॉफ ने यह उपलब्धि हासिल की थी।

एंड्रीवा ने अपने शुरुआती राउंड-रॉबिन मैच में एलिना स्वितोलिना को 6-4, 6-0 से हराने के साथ ही एक और रिकार्ड अपने नाम किया है। एंड्रीवा टूर्नामेंट के इतिहास में पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने अपने पहले दो डब्ल्यूटीए फाइनल्स मैचों में से प्रत्येक में 6-0 से एक सेट जीता है। इस डब्ल्यूटीए फाइनल्स में टॉप 10 में अपनी पहली जीत पक्की करने के बाद, एंड्रीवा ने इस सप्ताह दो और शीर्ष 10 खिलाड़ियों को हराया। यह उनके करियर में तीसरी बार है जब उन्होंने किसी एक ही इवेंट में कई शीर्ष 10 खिलाड़ियों को हराया है। इससे पहले उन्होंने 2025 में दुबई और इंडियन वेल्स में भी खिताबा जीता था।

वहीं हार के बाद भी सबालेंका बाहर नहीं हुई हैं और सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं। वह और एलिना स्वितोलिना शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टकरायेंगी। - स्वितोलिना ने अपने मुकाबले में कैरोलिना मुचोवा को एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 3-6, 6-2, 6-2 से हराया था। इस जीत के साथ, स्वितोलिना को शुक्रवार को सबालेंका के खिलाफ अपने ग्रुप स्टेज के फाइनल मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाने का अवसर मिलेगा।

यह डब्ल्यूटीए फाइनल्स में स्वितोलिना की 11वीं जीत थी और 2019 के बाद यह उनकी पहली जीत है। वह तीन सेट के मैचों में डब्ल्यूटीए फाइनल्स में 6-1 के प्रभावशाली रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ रही हैं। दूसरी ओर अपने दोनों मुकाबले हारने के कारण मुचोवा सेमीफाइनल की दौड़ समाप्त हो गई।



गुरमीत के लिए भावनाओं और लंबे जुड़ाव का सफर है मिर्जापुर

निर्देशक गुरमीत सिंह के लिए वेब सीरीज मिर्जापुर केवल एक सफल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भावनाओं और लंबे जुड़ाव का सफर है। गुरमीत सिंह का मानना है कि किसी भी फिल्म या सीरीज को बनाते समय सबसे जरूरी काम लेखक की मूल भावना को समझना और उसे पूरी ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारना है।

गुरमीत सिंह के मुताबिक, स्क्रिप्ट पढ़ते समय जो रोमांच और उत्साह महसूस होता है, वही अनुभव दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। गुरमीत सिंह ने मिर्जापुर फ्रेंचाइजी और इससे जुड़ी फिल्म के रचनात्मक पक्ष पर बात करते हुए बताया कि इसकी कहानी निर्देशक के सामने काम करने के लिए काफी सामग्री और चुनौतियां रखती है। ऐसे में उनका ध्यान दूसरी छोटी-छोटी बातों के बजाय कहानी की मूल भावना पर रहता है। उनके अनुसार, जब स्क्रिप्ट मजबूत होती है और उसमें दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता होती है, तो निर्देशक का मुख्य काम उसे सही तरीके से पर्दे पर प्रस्तुत करना होता है। उन्होंने बताया कि किसी भी कहानी को फिल्माने से पहले यह समझना जरूरी है कि लेखक ने कागज पर क्या लिखा है और उस विचार को दर्शकों के सामने किस रूप में पेश किया जा सकता है। वह चाहते थे कि स्क्रिप्ट पढ़ते समय उन्हें और उनकी टीम को जो उत्साह महसूस हुआ, वही उत्साह दर्शकों को भी देखने को मिले। उनके लिए निर्देशन का असली उद्देश्य कहानी के जादू को बिना अनावश्यक बदलाव के जीवंत करना है। गुरमीत सिंह ने यह भी बताया कि मिर्जापुर की शूटिंग उनके लिए तनावपूर्ण काम नहीं रही। कई वर्षों से इस फ्रेंचाइजी पर साथ काम करने के कारण पूरी टीम के बीच पारिवारिक रिश्ता बन गया है।

उन्होंने शूटिंग के अनुभव को दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने जैसा बताया। उनके मुताबिक, जब कलाकारों और तकनीकी टीम के सदस्य किसी कहानी से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, तो उनके बीच आपसी समझ और सहजता विकसित हो जाती है। निर्देशक ने कहा कि पूरी टीम ने इस फ्रेंचाइजी के लिए लगातार मेहनत की है। इसलिए जब भी वे इसके नए हिस्से की शूटिंग के लिए मिलते हैं, तो काम का माहौल बोझिल नहीं लगता। सभी लोग कहानी और अपने काम को लेकर उत्साहित रहते हैं। मिर्जापुर ने अपनी कहानी, किरदारों और रोमांच के कारण दर्शकों के बीच खास जगह बनाई है। अब इससे जुड़ी फिल्म को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है।



रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने ट्रंप ने भेजे अपने दो दूत, पुतिन से करेंगे सीधे बात

- इस प्रयास की नींव आबू धाबी में रखी गई, जहां रूस, यूक्रेन-अमेरिकी में हुई थी गुप्त बैठकें

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक पहल की है। उन्होंने अपने दो प्रमुख दूतों, दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को भेजा है, जहां वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने-सामने बातचीत करेंगे। जानकारों के मुताबिक अगले 48 घंटों में होने वाली इन बैठकों से यूरोप में जारी इस युद्ध को रोकने के लिए कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। यह अहम राजनयिक प्रयास रातों-रात शुरू नहीं हुआ। इसकी नींव कुछ दिन पहले आबू धाबी में रखी गई थी, जहां रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच दो दिनों तक गुप्त बैठकें हुई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक यह फरवरी के बाद पहला मौका था जब तीनों देशों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर युद्ध खत्म करने के विकल्पों पर मंथन कर रहे थे। जानकारों ने बताया कि कुशनर और विटकॉफ ने इन बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आबू धाबी से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद अब ये दूत सीधे मॉस्को पहुंच रहे हैं ताकि पुतिन के साथ शांति समझौते के जटिल पेंचों को सुलझाया जा सके। ट्रंप के इन दूतों का क्रेमलिन में सीधा प्रवेश इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को यात्रा से पहले, जेरेड कुशनर ने अपने बयानों में उम्मीद जताई कि उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच के अनसुलझे मुद्दों पर कुछ सकारात्मक खुले अवसर और उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि अब तक जिन मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ था, उन्हें तोड़ने का कोई रास्ता निकलता दिख रहा है। इस मिशन का एक रणनीतिक पहलू यह भी है कि मॉस्को में पुतिन से बातचीत करने के बाद, ये दोनों अमेरिकी दूत तुरंत आयरलैंड की राजधानी डबलिन जाएंगे। डबलिन में वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की टीम को मॉस्को की बैठक की पूरी जानकारी देंगे और रणनीति पर चर्चा करेंगे।

अमेरिका में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर की अचानक मौत, डेढ़ साल तक ही इस पद पर रहे

- रूसी विदेश मंत्रालय ने डारचीव को राजनयिक, अनुभवी नेता और दयालु सहकर्मी बताया

मास्को,एजेंसी। अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डारचीव (66) की अचानक मौत हो गई। मॉस्को में विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डारचीव इस पद पर केवल डेढ़ साल तक ही रहे। रूसी विदेश मंत्रालय ने डारचीव को एक बेहतरीन राजनयिक, अनुभवी नेता और दयालु सहकर्मी बताया है। उन्हें मार्च 2025 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। हालांकि मॉस्को ने उनकी मौत के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। इससे पहले डारचीव 2014 से 2021 तक कनाडा में रूस के राजदूत रह चुके थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलेक्जेंडर डारचीव को पिछले साल अमेरिका में इस पद पर नियुक्त किया गया था। यह समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के कुछ ही समय बाद का था, और यह उस दौर में हुआ जब यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान चल रहा था, जिसने रूस को पश्चिमी देशों के आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया। डारचीव रूस-अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ थे और 2021-2024 के बीच विदेश मंत्रालय के उत्तरी अमेरिकी विभाग के निदेशक रहे। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो डारचीव ने इस कदम को एक आवश्यक उपाय बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक डारचीव की मौत व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हफ्ते से भी कम समय बाद हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके में एक अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की गई थी।

बीजेपी विधानसभा चुनाव में कई एमएलसी को मैदान में उतारने पर कर रही विचार

-पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यूपी में उम्मीदवारों के चयन का बदलने जा रहा पूरा खाका



नई दिल्ली , एजेंसी। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यूपी में अपने उम्मीदवारों के चयन का पूरा खाका बदलने जा रहा है। पार्टी इस बार अपने ज्यादातर विधान परिषद सदस्यों को सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि बीजेपी आलाकमान ने अपने सभी एमएलसी को चुनाव की तैयारियों में जुटने और अपने-अपने प्रभाव वाले इलाकों में मजबूत जीत की संभावना वाली विधानसभा सीटों की पहचान शुरू करने का संदेश दे दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक इस संभावित फैसले से यूपी के कई बड़े मंत्रियों और सांगठनिक दिग्गजों की सीधी विधानसभा चुनाव में एंट्री होने जा रही है। जिन प्रमुख एमएलसी को चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चा है, उनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री एके शर्मा, जलशक्ति मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल हैं।
पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन अनुभवी नेताओं को सीधे जनता के बीच चुनावी मैदान में उतारने से राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह दोगुना होगा और उन क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। बीजेपी का यह नया दांव केवल एमएलसी को मैदान में उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पार्टी अपने मौजूदा विधायकों पर बड़े पैमाने पर गाज गिराने की तैयारी में है। जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी से निपटने के लिए बीजेपी 2027 में अपने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी आंतरिक सर्वे, क्षेत्रीय जातीय समीकरणों, जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शन और सांगठनिक फीडबैक के आधार पर ही अंतिम टिकट तय करेगी। एमएलसी को टिकट देने से जहां अनुभवी सांगठनिक नेताओं को सीधे विधानसभा में लाया जा सकेगा, वहीं कमजोर सीटों पर नए और मजबूत चेहरों को मौका देने की गुंजाइश भी बनेगी। यूपी बीजेपी की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति का सबसे अहम गढ़ है। 2027 के चुनाव से काफी पहले आलाकमान की तरफ से एमएलसी को तैयारी में जुटने के निर्देश देना यह साफ दर्शाता है कि बीजेपी इस बार किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

दिल्ली से गुजरात तक छठ पूजा की तैयारियां तेज, घाट पर किए खास इंतजाम

- अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पूजा में शामिल होंगे 25 हजार श्रद्धालु

नई दिल्ली , एजेंसी। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली से गुजरात तक तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में मुनक नहर के किनारे करीब 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट बनाया गया है। वहीं, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे तैयारी की गई हैं। दिल्ली में छठ पूजा के लिए मुनक नहर के किनारे बने घाट पर खास इंतजाम किए गए हैं। यहां साफ-सफाई, रोशनी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। घाट का उद्घाटन गुरुवार को किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद में भी छठ पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छठ महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष के मुताबिक इस बार शाम की पूजा में 25 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पिछले 25 साल से अहमदाबाद में छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि साबरमती नदी के किनारे छठ पूजा के लिए खास जगह तय कराने में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की पहल रही थी। इसके बाद आनंदीबेन पटेल ने इस घाट को मंजूरी दी और विजय रुपाणी सरकार के दौरान इसका उद्घाटन हुआ। अहमदाबाद में बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के करीब 10 लाख लोग रहते हैं। इनमें से कई लोग छठ पूजा के लिए अपने घर नहीं जा पाते। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए शहर में 10 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा के इंतजाम किए गए हैं। इस बार भी साबरमती रिवरफ्रंट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्य की उपासना करेंगे। दिल्ली की मुनक नहर से लेकर गुजरात के साबरमती तट तक छठ महापर्व की तैयारियां दिखाई दे रही हैं।

पीएम मोदी के बेंगलुरु और मैसूरु दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी, हजारों पुलिसकर्मी तैनात

- कई इलाके अस्थायी नो-फ्लाई जोन घोषित, ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुएं रहेंगी बैन

बेंगलुरु , एजेंसी। पीएम नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को प्रस्तावित कर्नाटक दौरे को देखते हुए बेंगलुरु और मैसूरु में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसपीजी की टीम भी पूरे सुरक्षा इंतजाम पर नजर रख रही है। पीएम के आने-जाने वाले रास्तों, कार्यक्रम स्थलों और आसपास के संवेदनशील इलाकों की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में तीन संयुक्त पुलिस आयुक्त, 15 पुलिस उपायुक्त, 20 सहायक पुलिस आयुक्त, 30 पुलिस निरीक्षक, 100 से ज्यादा उपनिरीक्षक और एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एसपीजी की टीम करीब 10 दिन पहले ही शहर पहुंच गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के काफिले के गुजरने वाले मार्गों पर स्थित ऊंची इमारतों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। आसपास के अपार्टमेंट की भी जांच की गई। पुलिस ने अपार्टमेंट प्रबंधन को निर्देश दिया है कि किसी भी नए या संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि की जानकारी तत्काल अधिकारियों को दें। इसके अलावा मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर उनकी कार्यक्षमता तय करें। सुरक्षा के मद्देनजर बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त ने शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक तीन तय स्थानों के एक किलोमीटर के दायरे में अस्थायी नो-फ्लाई जोन घोषित किया है। इस दौरान ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा। पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत आरए मंदुरकर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्रशिक्षण केंद्र परिसर के हेलीपैड से करेंगे। इसके बाद वे तावरेकेरे मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मैसूरु पहुंचकर चामुंडी पहाड़ी की तलहटी में विकसित भारत वन का उद्घाटन करेंगे। यह वन नम्मा मैसूरु, नम्मा कोडुगे पहल के तहत तैयार किया गया है। इसके अलावा वे भारत के पहले झुके हुए गुंबद वाले एलईडी तारामंडल का उद्घाटन करेंगे। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान और मैसूरु विश्वविद्यालय ने इसे 118 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। इसमें करीब 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली रवाना हो जाएंगे।

ओवैसी-आजाद ने बनाया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा

यूपी चुनाव में सीएम का चेहरा होंगे चंद्रशेखर

लखनऊ , एजेंसी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिलिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों दलों ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के नाम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। यह गठबंधन राज्य की करीब 150 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा।
जानकारी के अनुसार, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के बीच लखनऊ में करीब ढाई घंटे तक गहन बैठक चली, जिसके बाद इस गठबंधन पर सहमति बनी। इस सीट बंटवारे के तहत, आजाद समाज पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एआईएमआईएम 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। गठबंधन की औपचारिक घोषणा बृहस्पतिवार को लखनऊ में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की जाएगी, जहां दोनों नेता इसकी विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। इसके अलावा, 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली एक विशाल रैली में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होंगे, जो गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन का मंच होगा।
गठबंधन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनका मुख्य प्रयास युवाओं, किसानों तथा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मजबूत करना है। उन्होंने जोर दिया कि गरीबों के अधिकारों का हनन रोकने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, जो भी है, आपके सामने आ जाएगा। दोनों नेताओं का मानना है कि यह गठबंधन प्रदेश में सामाजिक न्याय की नई राजनीति की शुरुआत करेगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों ने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने के ओवैसी के प्रस्ताव में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ओवैसी ने इन पार्टियों को 2 अक्टूबर तक इस संबंध में फैसला लेने का समय दिया था, लेकिन उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला था। अब ओवैसी और



चंद्रशेखर आजाद का साथ आना प्रदेश की राजनीति में एक संभावित तीसरे मोर्चे की पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस नए गठबंधन की नजर विशेष रूप से राज्य के बड़े दलित और अल्पसंख्यक मतदाता वर्ग पर है, जो इसे चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण बना सकता है। फिलहाल, गठबंधन में अन्य छोटे दलों के शामिल होने की संभावना को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

अजित पवार प्लेन क्रैश: एनसीपी के शक ने महाराष्ट्र में मचाई खलबली

मुंबई,एजेंसी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रदेश प्रवक्ता उमेश पाटिल ने महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पाटिल ने इस हादसे को कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश करार दिया है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पास इस दावे को साबित करने वाला कोई पुख्ता सबूत फिलहाल मौजूद नहीं है। महाराष्ट्र के विभिन्न हलकों में इस क्रैश को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और सरकारी जांच एजेंसियां मामले की गहनता से पड़ताल कर रही हैं। पाटिल ने अपनी गट फीलिंग के आधार पर कहा, मेरे हिसाब से अजित दादा के साथ जो हुआ, वह हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। उन्होंने आगे बताया कि वे और पार्टी के कई सहयोगी पिछले 20 से 25 सालों से अजित पवार से जुड़े रहे हैं। अलग-अलग घटनाओं और परिस्थितियों को एक साथ जोड़ने पर उन्हें लगता है कि इसमें साजिश की पूरी संभावना है। पाटिल ने जोर देकर कहा कि प्लेन क्रैश के तकनीकी पहलुओं की पूरी जांच किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्होंने माना कि क्रैश की परिस्थितियों पर उनके भी कुछ सवाल हैं, लेकिन जांच काफी आगे बढ़ने के बाद ही कुछ और कहना सही होगा। यह घटना 28 जनवरी 2026 की है, जब अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। वे जिले की जिला परिषद चुनाव की रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वे दिल्ली की एक निजी चार्टर कंपनी वीएसआर वेंचर्स के बमबार्डियर लियरजेट 45 में सवार थे। विमान में अजित पवार समेत कुल पांच लोग यात्रा कर रहे थे। विमान ने सुबह करीब 8:10 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। बारामती एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के कारण पहली लैंडिंग की कोशिश असफल रही। दूसरी कोशिश के दौरान विमान रनवे थ्रेशोल्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें भीषण आग लग गई। इस दुखद हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

मेलोनी की कार में बम और स्कूलों को मिली धमकी से मचा हड़कंप



रोम, एजेंसी। इटली में 11 नवंबर का दिन उस समय दहशत भरा साबित हुआ, जब देशभर के कम से कम 300 स्कूलों को अचानक अजीबो-गरीब ईमेल्स मिलने लगे। इन ईमेल्स में स्कूलों में भीषण बम धमाके करने और इटली के लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाने जैसी खौफनाक धमकियां दी गई थीं। इन धमकियों ने न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, बल्कि सीधे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। ईमेल मिलते ही देश के 300 से ज्यादा स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया और पुलिस, बम निरोधक दस्ते तथा खुफिया एजेंसियां सभी कैंपसों की तलाशी में जुट गईं। धमकी में कहा गया था कि पीएम मेलोनी की कार में बम है।
इन धमकी भरे ईमेल्स में इटली के लोगों के 'नरसंहार' और हिंसा फैलाने की बात कही गई थी। मैसेज में दावा किया गया था कि स्कूल की इमारतों के अंदर एक 'पावरफुल विस्फोटक डिवाइस' रखी गई है, जिसे दूर बैठे ही रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जा सकता है। इन धमकियों का दायरा केवल स्कूलों और बच्चों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम सीधे तौर पर शामिल करते हुए लिखा गया था कि 'एक बम पीएम मेलोनी की कार के इंजन में भी फिट कर दिया गया है'। एक साथ देशभर के सैकड़ों स्कूलों और देश की प्रधानमंत्री को ऐसी सीधी धमकी मिलने से पूरी इतालवी सरकार में हड़कंप मच गया। स्कूलों और प्रशासन को भेजे गए इन सभी ईमेल्स के नीचे एक ही नाम लिखा हुआ था, 'मिखाइल एंड्रोपॉव, विलायत ऑफ मिसोगिनिस्तान का नेता'। हालांकि, इतालवी अधिकारियों के अनुसार, इस नाम या संस्था का कोई स्वतंत्र सत्यापन अभी तक नहीं हो सका है। जांच में यह भी सामने आया है कि यह कोई इकलौता मामला नहीं है। पिछले हफ्ते ही यूरोप के अन्य देशों, जैसे आयरलैंड और बुल्गारिया के मीडिया संस्थानों को भी इसी नाम से ऐसे ही धमकी भरे ईमेल्स मिले थे। एक ही नाम और एक ही भाषा के बार-बार इस्तेमाल से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यह यूरोप भर में डर फैलाने का एक बड़ा और सुनियोजित नेटवर्क हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इटली सरकार के मंत्री तुरंत हरकत में आ गए। इटली के शिक्षा मंत्री जुसेपे वालदितारा ने बताया कि देशभर में लगभग 300 धमकियां दर्ज की गई हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'यह साफ नजर आ रहा है कि इसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति काम कर रही है'।

वॉर मेमोरियल में फोटो खिंचवा रहे थे अमेरिका के रक्षामंत्री पीट हेगसेथ

हंसते ही सियोरिटी गार्ड ने लगा दी फटकार...पत्नी भी थी साथ, वीडियो वायरल

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ चर्चा में बने हुए हैं। महाभियोग से बचने के बाद अब वो एक नए विवाद में फंस गए हैं। दरअसल हेगसेथ अपने स्टाफ के साथ वेटरन्स डे समारोह पर वर्जीनिया स्थित आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री पहुंचे थे। यहां उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड ने फटकार लगा दी। आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पीट हेगसेथ टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर के सामने सीढ़ियों पर तस्वीरें खिंचवाते दिख रहे हैं। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी जेनिफर, चीफ ऑफ स्टाफ रिकी बुरिया, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ पैट्रिक वीवर और वरिष्ठ सलाहकार तमी राडाबाग भी नजर आए।



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीर खिंचवाने के बाद जैसे ही ये ग्रुप आगे बढ़ा, वहां किसी की जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। इसी दौरान मकबरे पर सुरक्षा में तैनात एक सैनिक ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के सलाहकारों और स्टाफ के ग्रुप को फटकार लगा दी। सैनिक ने सख्त लहजे में कहा कि सभी टूरिस्ट हर समय शांति और सम्मान का माहौल बनाए रखेंगे। इस मामले पर पेंटागन के शीर्ष प्रवक्ता सीन पार्नेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर दिन को मनाते समय, एक सैनिक ने सही और सम्मानजनक तरीके से सभी को मर्यादा बनाए रखने की याद दिलाई। रक्षा मंत्री और पूरे विभाग ने अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए हमारे सैन्य पुरुषों और महिलाओं के दिए गए बलिदानों का हमेशा सम्मान किया है और हमेशा करते रहेंगे।
बता दें यह मकबरा अमेरिका के सबसे पवित्र युद्ध स्मारकों में से एक है, जहां प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध के अज्ञात सैनिकों के अवशेष हैं। साल 1948 से सेना की तीसरी इन्फैंट्री रेजिमेंट के जवान हर मौसम में चौबीसों घंटे इसकी पहरेदारी करते हैं। वेटरन्स डे के कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हुए थे।
एक दिन पहले ही हेगसेथ अमरीकी कांग्रेस में अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव से बाल-बाल बचे थे। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी के लाए गए और डेमोक्रेट्स द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव को मंगलवार को रोक दिया गया था। हालांकि, जनवरी 2027 में संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होने के बाद उन पर फिर से महाभियोग का खतरा मंडरा सकता है।

अवैध संबंध से बच्चे को जन्म देने पर महिला को मिली 100 कोड़ों की सजा

दुबई , एजेंसी। रोजी-रोटी की तलाश में अपना देश छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब पहुंची केन्याई महिला एस्थर वांजा मुथोनी को वहां एक मिस्री शख्स के साथ शादी के बाहर संबंध बनाने और एक बच्चे को जन्म देने के मामले में 100 कोड़ों की सजा सुनाई गई है। सऊदी अरब में घरेलू कामगार के तौर पर काम कर रही मुथोनी की जिंदगी तब एक अनचाहे तूफान से घिर गई, जब बच्चे के जन्म के बाद यह मामला अथॉरिटीज तक पहुंच गया। वह हाउसकीपर और नैनी का काम करती थी और किसी तरह अपनी जिंदगी चला रही थी। एस्थर वांजा मुथोनी का इसी दौरान एक मिस्री शख्स से रिश्ता बना और वह गर्भवती हो गईं। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। समस्या तब शुरू हुई जब मुथोनी ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। सऊदी अरब के कानून के तहत, अस्पतालों को शादी के बाहर बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं की जानकारी अधिकारियों को देना अनिवार्य होता है।

डेमोक्रेटिक के दिग्गज सांसदों ने ईरान युद्ध को खत्म करने का बनाया दबाव

वाशिंगटन, एजेंसी। कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े सैन्य दिग्गज सांसदों और हाल ही में निर्वाचित उनके सहयोगियों ने ईरान युद्ध को खत्म करने की मांग की है। वहीं उनकी पार्टी ने वेटरन्स डे के अवसर पर सैन्य कर्मियों के लिए ज्यादा मजबूत सुरक्षा उपायों और पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य सेवा लाभों तक व्यापक पहुंच की वकालत की है। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि और इराक युद्ध के पूर्व सैनिक क्रिस डेलूजियो ने युद्ध खत्म करने और पूर्व सैनिकों के साथ खड़े होने की अपील के तहत संयुक्त बयान की घोषणा की।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष केन मार्टिन और पार्टी की वेटरन्स एंड मिलिट्री फैमिलीज काउंसिल के सह-अध्यक्ष ऑटो ली और मार्ज हॉफा ने कहा कि सैन्य सेवा का सम्मान करने का अर्थ उन फैसलों की समीक्षा करना है, जो सैनिकों को खतरे में डालते हैं। उन्होंने संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों के साथ-साथ जीवनयापन की लागत कम करने, स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने और सैन्य परिवारों की सुरक्षा मजबूत करने का संकल्प लिया। सीनेटर टैमी डकवर्थ ने कांग्रेस से ईरान युद्ध के दौरान विषैले पदार्थों के संपर्क में आए पूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षा प्रावधानों का विस्तार करने वाला कानून पारित करने की अपील की। डेमोक्रेटिक सांसद टैमी डकवर्थ ने कहा कि उनका प्रस्तावित न्यू पैक्ट फॉर ईरान वेटरन्स एक्ट उन कमियों को दूर करेगा, जिनकी वजह से युद्ध से लौटे सैन्यकर्मियों को स्वास्थ्य सेवाएं और लाभ पाने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उनके कार्यालय के मुताबिक यह प्रस्ताव ईरान में सेवा देने वाले सैनिकों, जिनमें उसके वायुक्षेत्र और क्षेत्रीय जलक्षेत्र में तैनात कर्मी भी शामिल हैं, के लिए विषैले पदार्थों के संपर्क में आने की कानूनी मान्यता स्थापित करेगा।
डकवर्थ ने कहा कि किसी भी सैनिक को विदेश में युद्ध लड़ने के बाद घर लौटकर उस देखभाल और सुविधाओं के लिए दूसरी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, जिसके वे अपनी सेवा के आधार पर हकदार हैं। यह प्रस्ताव फिलहाल विधायी प्रक्रिया में है। वेटरन्स डे पर उनकी अपील का उद्देश्य कांग्रेस से इसे पारित कराने का समर्थन जुटाना था, न कि यह घोषणा करना कि ये अतिरिक्त सुरक्षा उपाय पहले ही लागू हो चुके हैं। इस बीच ट्रंप की पूर्व सैनिकों के समर्थन संबंधी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। आर्लिंग्टन नेशनल सेमेट्री में अपने संबोधन में कहा कि जब तक मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, हम हमेशा उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

नेक्सटऐज मीडिया एंड कांलटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए, प्रकाशक, संपादक अनीता यादव द्वारा मुद्रक, रजनी कुमारी मेसेर्स साईं प्रिंटिंग प्रेस डी-85 सेक्टर-06 201301 से मुद्रित कराकर 962 सरफाबाद सेक्टर-73, नोएडा-201304 से प्रकाशित किया,
प्रधान संपादक : रिंकू यादव संपादक : अनीता यादव PRGI No. UPHIN/26/A8255 Ph. : 4403949, Email : unplugindia26@gmail.com